

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15012025-260246  
SG-DL-E-15012025-260246असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2025/ पौष 23, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 339
No. 22]	DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2025/ PAUSHA 23, 1946	[N. C. T. D. No. 339

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय  
अधिसूचना

दिल्ली, 9 जनवरी, 2025

फा.सं. जी.जी.एस.आई.पी.यू./सम./79वीं प्रबं.मं./अधि.12 (संशो.)/2023-24/434 गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का 9) की धारा 27 के प्रावधानों के अनुपालन में गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल ने दिनांक 28 वीं अप्रैल 2023 वीं अप्रैल 2023 को आयोजित अपनी 79 वीं बैठक में कार्यसूची मद सं. 79•13 के द्वारा, 'विद्या वाचस्पति उपाधि (डॉक्टर ऑफ फिलासफी डिग्री)' अर्हता के लिये शासी कार्यक्रमों जिन्हें संख्या आई पीवी/जेआर(सी)/बी ओ एम 48/2011/531 दिनांक 24•09•2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया था, से संबंधित अध्यादेश 12 को संशोधित कर दिया है जिससे संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं:

**अध्यादेश 12:** विद्या वाचस्पति उपाधि (डॉक्टर ऑफ फिलासफी डिग्री) की अर्हता के लिये शासी कार्यक्रम।

**अनुप्रयोज्यता:** यह अध्यादेश विद्या वाचस्पति उपाधि की अर्हता के लिये समस्त शासी कार्यक्रमों (शैक्षिक सत्र 2023-24 से पर अनुप्रयोज्य) लागू होगा। यह अध्यादेश, प्रबंध मण्डल द्वारा दी गयी स्वीकृति की तिथि से ही प्रभावी हो जायेगा।

**1•0 परिभाषाएँ**

- 1•1 "अधिनियम" से अभिप्राय होगा समय-समय पर यथा संशोधित गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम 1998
- 1•2 "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय होगा गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली।
- 1•3 "अध्ययन स्कूल" से अभिप्राय होगा स्कूल (स्कूल्स) अथवा विश्वविद्यालय अध्ययन स्कूल (यूएसएस) जो कि अध्यादेश 2 के खण्ड 1•0 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये होंगे।
- 1•4 "केन्द्र" से मन्तव्य होगा, अध्यादेश 35 के खंड 1 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित 'उत्कृष्टता-केन्द्र'।
- 1•5 "महाविद्यालय/संस्थान" से अभिप्राय होगा एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अपने विशेषाधिकारों के द्वारा अनुरक्षित अथवा स्वीकृत किया गया हो और जो अधिनियम की धारा 2(i) में परिभाषितानुसार किसी संबद्ध महाविद्यालय /संस्थान को सम्मिलित करता हो तथा इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार विद्या वाचस्पति कार्यक्रम के लिये स्वीकृत हो।
- 1•6 "पाठ्य समिति (बीओएस)" का वही अभिप्राय होगा जैसा कि संबंधित विद्याध्ययन के विश्वविद्यालयी स्कूलों के अध्यादेश 2 खण्ड 2 के अंतर्गत पाठ्य समिति के बोर्ड की परिभाषित किया गया होगा। इसके साथ-साथ 'पाठ्य समिति' शब्दावली का उपयोग केन्द्र(ी) की संचालन समिति पर भी लागू होगा। संचालन समिति की भूमिका, अध्यादेश 35 में परिभाषित इसकी भूमिका के अतिरिक्त, पाठ्य समिति की भूमिका के समान ही होगी। इसके अतिरिक्त, संचालन समिति का गठन भी अध्यादेश 35 में परिभाषितानुसार ही होगा। जहाँ कहीं भी 'पाठ्य समिति' शब्द का उल्लेख इस अध्यादेश में किया गया है, भविष्य में, अध्यादेश 35 के अन्तर्गत गठित केन्द्रों के संदर्भ में इसे संचालन समिति के रूप में ही पढ़ा/जाना जायेगा।
- 1•7 "अनुसंधान तथा विकास प्रकोष्ठ" (आर डी सी) का अभिप्राय होगा विश्वविद्यालय का अनुसंधान तथा विकास प्रकोष्ठ।
- 1•8 "पाठ्यक्रम कार्य" से अभिप्राय होगा, विद्यावाचस्पति उपाधि (पी एच•डी डिग्री) के लिये पंजीकृत छात्र द्वारा अपनाये जाने के लिये स्कूल /विभाग/ केन्द्र द्वारा, निर्धारित अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम।
- 1•9 "परीक्षा नियंत्रक (सी ओ ई)" से अभिप्राय होगा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक।
- 1•10 "विद्या विशेष" का अभिप्राय होगा वे 'विषय विशेष' जिनमें, विद्या वाचस्पति उपाधि प्रमाण पत्र में उद्धृतानुसार विद्यावाचस्पति की उपाधि प्रदान की जानी है। "स्कूल शोध समिति" (एस आर सी) संस्तुति करेगा और संबंधित स्कूल की पाठ्य समिति उस 'विषय-विशेष' की स्वीकृति देगी जिसमें स्कूल के माध्यम से विद्यावाचस्पति की उपाधि प्रदान की जायेगी। संबंधित स्कूल के अधिष्ठाता (डीन), स्कूल में जो विद्या वाचस्पति उपाधि प्रदान करने के लिये पाठ्य समिति की स्वीकृति के पश्चात् विषय विशेष प्रस्तावित किये जाने हैं, अधिसूचना हेतु शोध एवं विकास अनुभाग को सूचित करेंगे।
- 1•11 "शैक्षिक सत्र" एक वर्षीय अवधि का होगा जो छः-छः मास के दो सत्रों में प्रभाजित होगा। शैक्षिक सत्र सामान्यतः प्रतिवर्ष के अगस्त मास के प्रथम कार्य दिवस से प्रारम्भ होगा। विद्यावाचस्पति कार्यक्रम के पाठ्यक्रम कार्य वाले भाग के संचालन के लिये विस्तृत शैक्षिक कलैन्डर को शोध एवं विकास अनुभाग अधिसूचित करेगा जबकि विद्यावाचस्पति शोध निबंध/शोध प्रबंध कार्य की समीक्षा के लिये शैक्षिक कलैन्डर को संबंधित कलैन्डर को संबंधित स्कू•शो•स• (एस आर सी) अधिसूचित करेगी।

- 1•12 "शोध छात्र" से अभिप्राय होगा एक ऐसा व्यक्ति, जो इस अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत विद्यावाचस्पति के लिए पंजीकृत है और इसे छात्र भी उल्लिखित किया जायेगा।
- 1•13 "विदेशी शोध छात्र" से अभिप्राय होगा भारतीय मूल के ऐसे विदेशी नागरिक अथवा व्यक्ति जो इस अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत विद्यावाचस्पति के लिये शोध छात्र के रूप में पंजीकृत हैं।
- 1•14 "विदेशी शिक्षण संस्थान" से अभिप्राय होगा (i) एक ऐसा संस्थान जो अपने गृह देश में विधिवत् रूप से स्थापित अथवा निगमित है और अपने गृह देश में पूर्व स्नातक परास्नातक और उच्च स्तरीय शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध करा रहा है (ii) जो पारंपरिक रूप से आमने-सामने डिग्री प्रदान कराने वाली शिक्षा प्रदान कराता है लेकिन दूरस्थ, ऑन लाईन और ओडीएल विधि को उपयोग में नहीं लाता।
- 1•15 "भावहरण (साहित्यिक चोरी)" से अभिप्राय है किसी अन्य के कार्य या भावों की चोरी करना और फिर उन्हें अपना बताकर प्रस्तुत करना।
- 1•16 "अनुबद्ध शिक्षण स्टाफ" से अभिप्राय है अंश-कालिक अथवा आकस्मिक अनुदेशक लेकिन ऐसा पूर्ण कालिक शिक्षण स्टाफ नहीं जिसे गुरु गोबिन्द सिंह विश्वविद्यालय में शिक्षण हेतु किराये पर लिया जाये।
- 1•17 "पर्यवेक्षक" से अभिप्राय होगा इस अध्यादेश में अनुबंधितानुसार विश्वविद्यालय अथवा संबद्ध महाविद्यालय के अर्हता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण सदस्य।
- 1•18 "सह-पर्यवेक्षक" से अभिप्राय है इस अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत शोध-छात्र के लिये समनुदेशित अतिरिक्त पर्यवेक्षक।
- 1•19 "अभिक्षक पर्यवेक्षक" से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत, वास्तविक पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में शोध छात्र के हित में उसके पर्यवेक्षक की भूमिका का निर्वाह करने के लिए एक अन्य वैकल्पिक पर्यवेक्षक नियत करना।
- 1•20 "स्कूल शोधसमिति (एस आर सी /स्कू•शो•स•)" का अर्थ है एक ऐसी स्कूल शोध समिति जिसमें संबंधित स्कूल के अधिष्ठाता अध्यक्ष के रूप में और स्कूल के माध्यम से विद्या वाचस्पति कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये विषय(ि) के विश्वविद्यालय से जुड़े सभी मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक सम्मिलित होंगे। बहुविधि विषयों में विद्यावाचस्पति की उपाधि प्रस्तावित करने वाले स्कूलों में प्रत्येक ऐसे विषय, जैसी आवश्यकता हो, के लिये अलग से स्कूल शोध समिति होनी चाहिये, साथ ही इस प्रकार की समितियों में संबंधित विषयों के न्यूनतम तीन सदस्य होने चाहिये। इसके अतिरिक्त संबंधित स्कूल की ऐसी सभी विषय-विनिर्दिष्ट स्कूल शोध समितियों में न्यूनतम दो समान सदस्य होने चाहियें इसमें पारिभाषिक शब्द 'एस आर सी' केन्द्र की केन्द्रीय शोध एवं परामर्शी समिति (सी आर सी सी) पर भी लागू होता है। सी आर सी सी की भूमिका, उपरोक्त विवरणानुसार एस आर सी की भूमिका के समान होगी, जो अध्यादेश 35 में विवरणित इसकी अपनी भूमिका के अतिरिक्त होगी। इसके बाद, अध्यादेश में जहाँ कहीं भी एस आर सी शब्दावली का उपयोग होगा, उसे अध्यादेश 35 के अन्तर्गत गठित केन्द्र के संदर्भ में सी आर सी सी के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिये।
- 1•21 "प्रवेश समिति" से अभिप्राय उस समिति से है जिसमें किसी स्कूल/विषय-विशेष में खाली स्थानों के साथ, सभी भावी (स्वीकृत) पर्यवेक्षक सम्मिलित होंगे, और जो उस प्रवेश सत्रक में शोध छात्रों को लेने के इच्छुक होंगे, जिनकी न्यूनतम संख्या 5 सदस्यों की होगी जिसमें एक अधिष्ठाता और अनु• जाति/अनु• जनजाति वर्ग से एक सदस्य होगा। एस आर सी, प्रवेश समिति का गठन करेगी। मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक होने अथवा उस वर्ष के लिये स्थान रिक्त होने, या उसी स्कूल अथवा विषय विशेष के साथ संबंधित होने की सभी शर्तों में ढील दी जा सकती है, यदि आवश्यक हो तो, अनु•जा•/अनु• जन जाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये, एस आर सी का अभिलिखित निर्णय आवश्यक होगा।

यदि इस समिति के गठन के लिये कुल उपलब्ध सदस्यों की संख्या 5 से कम रह जाती है तो एस आर सी के लिखित निर्णय के माध्यम से, संबद्ध विषय-विशेष में कार्यक्रम प्रस्तावित करने वाले विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर किसी अन्य विश्वविद्यालयी स्कूल/केन्द्र से अथवा स्कूल से ही अन्य मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षकों को सहयोजित किया जा सकेगा। समिति की अध्यक्षता संबंधित स्कूल के अधिष्ठाता (डीन) करेंगे और वे ही किसी विशेष शैक्षिक सत्रक में विद्या वाचस्पति (पी एच डी) हेतु चयनित शोध छात्रों के साक्षात्कार और आबंटन के लिये उत्तरदायी होंगे।

1•22 "बाह्य परीक्षक" से अभिप्राय प्रकाशित शोधकार्य धारक एक ऐसा विद्वान (अकादमिक सदस्य)/शोधकर्ता, जो उस विश्वविद्यालय का भाग नहीं होगा जिसमें विद्या वाचस्पति कार्यक्रम के जिसे विद्या वाचस्पति शोधकर्ता ने स्वयं को पंजीकृत कराया हुआ है तथा जैसा भी इस अध्यादेश में और भी अधिक वर्णित हैं।

1•23 "आयोग" से इस अध्यादेश में अभिप्रेत होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

1•24 "सैट" का अर्थ होगा विद्यावाचस्पति प्रवेश परीक्षा (पीएचडी एन्ट्रेंस टैस्ट) जिसका संचालन विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा द्वारा किया जायेगा।

1•25 "आर ए सी" का अर्थ होगा शोध परामर्श समिति (रिसर्च एडवाइजरी कमेटी)।

**टिप्पणी:** इस अध्यादेश में जहाँ कहीं भी 'वह (ही)' और 'उसका (हिज़)' शब्द आया है, इसका क्रमशः निहितार्थ होगा 'वह (पु.)/वह (स्त्री.)' तथा 'उसका/उसकी'।

## 2•0 विद्या वाचस्पति कार्यक्रम(ों) में प्रवेश के लिये न्यूनतम पात्रता मापदण्ड

2•1 विद्या वाचस्पति कार्यक्रम में निम्न प्रवेशेच्छु पात्र होंगे:

2•1•1 ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने कुल योग के न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा जहाँ श्रेणी प्रणाली का अनुपालन किया जाता है, वहाँ अंक मापक्रम में समान श्रेणी के साथ, 4 वर्षीय/8-सत्रक वाले स्नातक डिग्री कार्यक्रम के बाद, 1 वर्षीय/2-सत्रक की निष्णात डिग्री पूर्ण कर ली हो; अथवा

2•1•2 ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने कुल योग के न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा जहाँ श्रेणी प्रणाली का अनुपालन किया जाता है, वहाँ अंक मापक्रम में समान श्रेणी के साथ 3 वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 2-वर्षीय/4-सत्रक निष्णात उपाधि कार्यक्रम पूर्ण कर लिया हो अथवा तदनुरूप विनियामक निकाय द्वारा निष्णात कार्यक्रम के समतुल्य घोषित अर्हता प्राप्त कर ली हो; अथवा

2•1•3 ऐसे अभ्यर्थी, जो 4-वर्षीय/8 सत्रक स्नातक की उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश-इच्छुक हैं, को सकल योग के न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक धारक अथवा जहाँ पर श्रेणी प्रणाली का अनुपालन किया जाता है, वहाँ अंक मापक्रम में समतुल्य श्रेणी धारक होना चाहिये; अथवा

2•1•4 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कुल योग के न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा जहाँ श्रेणी प्रणाली का अनुपालन किया जाता है, वहाँ अंक मरनक्रम में समान श्रेणी के साथ दर्शन निष्णात/विद्या निष्णात (एम0फिल) कार्यक्रम पूरा कर लिया हो; अथवा

2•1•5 ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने किसी शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता और मानक को सुनिश्चित करने अथवा प्रत्यायित, निर्धारण करने के लिये उस देश में किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी अथवा उस गृह देश में विधि के अन्तर्गत स्थापित अथवा समाविष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत, मान्यता प्रदत्त, प्राधिकृत किसी विदेशी संस्थान से समरूप अर्हता प्राप्त की हो।

2•1•6 ऐसे मामलों में, जहाँ कि उपाधि (डिग्री) प्रदाता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अर्हक परीक्षा के अंक प्रदान नहीं किये गये जैसे कि दंत शल्य चिकित्सा निष्णात (एम0डी0एस0), एम0डी; डी0एम0, विज्ञान निष्णात (एम0एस0) रसायन निष्णात (एम0सी एच0) आदि, वहाँ उन अभ्यर्थियों, जिन्होंने सुसंगत स्नातक पूर्व परीक्षा में कुल योग के न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक, अथवा जहाँ श्रेणी प्रणाली का अनुपालन किया जाता है, वहाँ अंक मापक्रम में समान श्रेणी अर्जित की है, पर विद्या वाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेशार्थी के पात्र के रूप विचार किया जायेगा।

ऐसे मामले में, सम्बन्धित अभ्यर्थी को एक वचन बंध इस आशय का देना पड़ेगा कि उनका विश्वविद्यालय/संस्थान कथित अर्हक परीक्षा के लिये अंक प्रदान नहीं करता है।

2•2 अनु0जाति/ अनु0जन जाति /अन्य पिछड़ी जातियों (नवोन्नत इतर वर्ग) /अन्यथा सक्षम /आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप अभ्यर्थियों की अन्य श्रेणियों से जुड़े अभ्यर्थियों को अंकों अथवा इनके तुल्य श्रेणी में 5 प्रतिशत की छूट अनुमेय होगी।

2•3 प्रत्येक स्कूल के स्कूल शोध अनुभाग उन विस्तृत पात्रता मापदंडों को परिभाषित करेंगे जिन्हें कम से कम इस अध्यादेश के विनिर्देशों के व्यापक आनुरूप्य में होना चाहिये, और जिन्हें अध्ययन मंडल की स्वीकृति के बाद, प्रवेश विवरणिका में सम्मिलित करने के लिये शोध एवं विकास विभाग को भेज दिया जायेगा।

### 3•0 प्रवेश प्रक्रिया

3•1 अध्ययनों के विद्या वाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेश, शिक्षण के संबंधित विषय(i) में विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक वर्ष में एक बार आयोजित एक प्रवेश परीक्षा पीएचडी एन्ट्रेन्स टेस्ट (पीईटी) के माध्यम से होगा।

3•2 ऐसे छात्रों, जो यूजीसी-नैट (जेआरएफ/यूजीसी-सी एस आई आर नैट(जेआर एफ)/गेट/सीईईडी तथा समरूप राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिये अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, को विद्यावाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेशार्थ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश-परीक्षा से छूट दी जायेगी। तथापि, जब भी विद्या वाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय आवेदन आमंत्रित करता है तो विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये उन्हें आवेदन करना होगा।

3•3 प्रत्येक स्कूल के स्कूल शोध अनुभाग उन विषयों को निर्दिष्ट करेंगे जिन में संबंधित स्कूल में विद्यावाचस्पति कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है और अध्ययन मंडल की स्वीकृति के बाद, प्रवेश विवरणिका में सम्मिलित करने के लिये उसे सम्मिलित करने के लिये शोध एवं विकास विभाग को भेज दिया जायेगा। विद्या वाचस्पति कार्यक्रम के लिये अध्ययन का विषय केवल एक स्कूल द्वारा ही प्रस्तावित किया जायेगा। यदि, अध्ययन के एक ही विषय को एकाधिक स्कूल प्रस्तावित करने के इच्छुक हैं तो मामले को विद्वत परिषद् के समक्ष उसके विचारार्थ और संकल्प हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। विद्वत परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

3•4 विद्या वाचस्पति कार्यक्रम के लिये प्रवेश विवरणिका में, प्रवेश के लिये उपलब्ध रिक्तियों (सीट्स) की संख्या, विषय/विद्या विशेषानुसार उपलब्ध सीटों का वितरण, प्रवेश के लिये मानदण्ड, प्रवेश संबंधी प्रक्रिया तथा वि0वा0प्र0प0 (पीईटी) आयोजित करने के लिये कार्यरिती एवं अभ्यर्थियों के हितार्थ अन्य सभी संबंधी सूचनाएँ विनिर्दिष्ट होगी।

3•5 विद्यावाचस्पति के लिये विशिष्ट विद्या विशेष में उपलब्ध सीटों (अंतरिम) की संख्या, विद्या वाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेश हेतु जारी की गयी प्रवेश विवरणिका का भाग होगी। सम्बन्धित विद्या विशेष का स्कूल, शोध अनुभाग उपलब्ध शोध पर्यवेक्षक एवं अन्य उपलब्ध शैक्षिक तथा भौतिक सुविधाओं पर आधारित एक शैक्षिक सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्या वाचस्पति छात्रों के पूर्व निर्धारित एवं प्रबन्धनीय

संख्या का, वार्षिक आधार पर निर्धारण करेगा। विद्या वाचस्पति कार्यक्रम में शोध छात्रों के प्रवेश के लिये स्लाट्स/स्थानों की कुल संख्या में संबंधित वि०अध्य०स्कूल (यू एस एस)/केन्द्र द्वारा वृद्धि की जा सकेगी। तथापि, यह वृद्धि उन पर्यवेक्षकों के अधीन स्लाट्स/सीट के लिये सीमित होगी जिन्होंने, किसी विशिष्ट विद्या विशेष में प्रवेशार्थ अ-शून्य स्लाट्स/स्थान, प्रदान किये होंगे। विश्वविद्यालय की वेब साइट पर, संबंधित वि०अध्य० स्कूल/केन्द्र द्वारा उपलब्ध रिक्त स्लाट्स/स्थानों की अंतिम सूची के साथ-साथ विद्यावाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित साक्षात्कार की अनुसूची प्रदर्शित की जायेगी।

- 3•6 आरक्षण, राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार होगा, जिसे समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
- 3•7 विद्या वाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विज्ञापन और विवरणिका, निदेशक, आर डी सी द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा और विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद इसे सार्वजनित कर दिया जायेगा।
- 3•8 विद्या वाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेशार्थ विज्ञापन कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दिया जायेगा जिसमें से कम से कम एक हिन्दी भाषा में होना चाहिये।
- 3•9 प्रवेश परीक्षा तालिका में 50% अंक, शोध विधि के होंगे और 50% विनिर्दिष्ट विषय के होंगे। लिखित प्रवेश परीक्षा विद्या वाचस्पति कार्यक्रम में अर्हक विच्छेदक के रूप में 50% अंक होंगे। समय-समय पर आयोग के निर्णय के अनुसार अनु०जाति/ अनु०जन जाति/अन्य पि० वर्ग/ दिव्यांग श्रेणी /आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०) तथा अभ्यर्थियों की अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में 5% अंकों की छूट अनुमत होगी।
- 3•10 लिखित परीक्षा के लिये विस्तारित पाठ्यक्रम संबंधित विषय की स्कूल शो०समि० द्वारा स्वीकृत होगा तथा प्रवेश विवरणिका में सम्मिलित करने के लिये अनु० तथा वि०प्रको० को अग्रेषित कर दिया जायेगा।
- 3•11 प्रत्येक वि०वि०अध्य०स्कूल के विशिष्ट विद्या के संबंधित स्कू०शो०समि० प्रत्येक शिक्षण सत्र में उपलब्ध विद्या वाचस्पति सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले पात्र छात्रों की संख्या निर्धारित करेंगे। विद्यावाचस्पति कार्यक्रम के विषय विशेष के पात्र छात्रों की उपलब्धता और आरक्षण की श्रेणी, न्यूनतम सीट/स्लॉट : छात्र अनुपात 1:3 होगा। यदि छात्र संख्या विनिर्दिष्ट अनुपात (1:3) से कम होगा तो सभी पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा।
- 3•12 साक्षात्कार का आयोजन किया जायेगा, जहाँ अभ्यर्थियों से अपेक्षा होगी कि वे एक विधिवत् गठित प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुति के माध्यम से अपनी शोध रुचि/क्षेत्र पर चर्चा करें।
- 3•13 प्रवेश, संबंधित स्कूल की प्रवेश समिति द्वारा संचालित साक्षात्कार में प्रदर्शन/छात्र की योग्यता पर आधारित होगा। साक्षात्कार निम्न पहलुओं पर विचार करेगा, अर्थात् क्या

- (क) छात्र के पास प्रस्तावित शोध कार्य से संबंधित मूल जानकारी और अभिज्ञता है ;
- (ख) अभ्यर्थी के पास प्रस्तावित शोध कार्य निष्पादन करने की सक्षमता है;
- (ग) प्रस्तावित शोध-योजना, शोध खेत्र में नवीन/परिवर्धित ज्ञानार्जन में सहायक हो सकती हैं

लिखित प्रवेश परीक्षा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिये, योग्यता क्रम सूची (100 अंकों में से) उन अभ्यर्थियों हेतु तैयार की जायेगी जिनके शोध-प्रस्तावों को प्रवेश समिति द्वारा निम्न मानदण्डानुसार स्वीकार कर लिया गया होगा।

- (i) लिखित प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों को 70% महत्त्व (वेटिज) दिया जायेगा:

(ii) साक्षात्कार को 30% महत्त्व (वेटिज) दिया जायेगा।

लिखित प्रवेश परीक्षा से छूट प्रदत्त उन अभ्यर्थियों, जिनके शोध प्रस्तावों को प्रवेश समिति ने स्वीकार कर लिया हो की योग्यता क्रम सूची उपरोक्त खण्ड 3.13(ii) में सूचीबद्ध अंकों, जिनका मान 100 अंक होगा, के आधार पर तैयार की जायेगी।

3.14 चयनित शोध छात्र के लिये शोध पर्यवेक्षक के नियतन का निर्णय प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा जो प्रति पर्यवेक्षक के अधीन शोध छात्रों की संख्या, पर्यवेक्षकों में उपलब्ध विशेषज्ञता तथा साक्षात्कार के समय शोध-छात्र द्वारा प्रदर्शित शोध संबंधी रुचि पर निर्भर करेगा। रिक्तियों (सीटों) का आबंटन (नियतन) योग्यता और आरक्षण नीति का आधारित होगा।

3.15 प्रवेश समिति, वि०वा०प्र०परी०(पी०ई०टी०) एवं/अथवा साक्षात्कार आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम योग्यता सूची संबंधित स्कूल शो० समि० को उसके विचारार्थ और स्वीकृति हेतु प्रस्तावित करेगी। संबंधित विषय की स्कूल शो०स० द्वारा स्वीकृति के उपरान्त इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर संबंधित वि०वि० अ० स्कूल द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा और तत्पश्चात् सभी प्रवेश औपचारिकताएँ प्रवेश समिति द्वारा पूर्ण की जायेंगी। बाद में, प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूची नामांकन जारी किये जाने के लिये अनु० तथा वि०प्रको० को अग्रेषित कर दी जायेगी।

3.16 विद्या वाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेश, पूर्ण कालिक/अंश कालिक विधि में अनुमत होगा। संबंधित स्कूल शोध समिति की निर्णय लेगी कि किसी विषय-विशेष में प्रवेश, दोनों अथवा एक विधि में अनुमत होगा। प्रवेश पुस्तिका में सम्मिलित किये जाने के लिये यह सूचना अनु० तथा वि०प्रको० को प्रेषित कर दी जायेगी।

3.17 विश्वविद्यालय स्कूलों अथवा सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों के ऐसे स्थायी शिक्षण सदस्यों सहित नियोजित अभ्यर्थियों, जो विद्या वाच० में पूर्ण कालिक शोध छात्र के रूप में प्रवेश लेने के इच्छुक होंगे, को विश्वविद्यालय को न्यूनतम पंजीकरण अवधि के पालन हेतु न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिये अवकाश लेना होगा। अपने नियोजकों से अवकाश प्राप्त करने के लिये जिन अभ्यर्थियों को चयन के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, वे इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित चयन प्रवेश सूची का उपयोग कर सकेंगे परन्तु, प्रवेश की स्वीकृति केवल अवकाश मंजूरी पत्र की मूल प्रति जमा कराने के बाद ही प्रदान की जायेगी।

3.18 नियमित नियोजन में नियोजित सभी अभ्यर्थियों (पूर्ण कालिक/अंश कालिक) को वि० वाच० कार्यक्रम के अनुपालन के उद्देश्य से अपने नियोजन संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "निरापत्ति प्रमाण पत्र" जमा कराना होगा। जारी "निरापत्ति प्रमाण पत्र" में निम्न का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये:

- (i) कि अभ्यर्थी को पूर्णकालिक/अंशकालिक आधार पर अध्ययन जारी करने की अनुमति दी जाती है।
- (ii) कि उसकी कार्यालयी ड्यूटी, उसको शोध कार्य में पर्याप्त समय लगाने की अनुमति देती है
- (iii) कि यदि आवश्यकता हुई, तो उसे अपना पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करने के लिये ड्यूटी से मुक्त कर दिया जायेगा।

उक्त "निरापत्ति प्रमाण पत्र" प्रवेशार्थ साक्षात्कार के समय विद्या वाच० प्रवेश समिति को सौंपना होगा

3.19 गु०गो०सिंह इ०प्र० विश्वविद्यालय की शोध परियोजनाओं में कार्यरत सभी कर्मचारीगण इस शर्त के साथ गु०गो०सिंह इ०प्र०वि०वि० में पूर्णकालिक विद्या०वाच० का निर्वहन कर सकते हैं कि वे गु०गो०सिंह इ०प्र०वि० विद्यालय के विद्या वाच० कार्यक्रम में प्रवेशार्थ सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। तथापि, उन्हें उस शोध परियोजना, जिसमें वे विद्या वाच० कार्यक्रम का अनुपालन कर रहे हैं के संबंधित प्रधान

अन्वेषक (पीआई) से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा और उसे प्रवेशार्थ साक्षात्कार के समय जमा कराना होगा।

3•20 प्रवेश समिति, प्रवेश विवरणिका में अतधिसूचित किसी विषय विशेष में विज्ञापित सभी/किसी एक सीटों/स्लाटों को न भरने का भी निर्णय ले सकती है।

3•21 विश्वविद्यालय का अनु० एवं शोध प्रको० अपनी वैबसाइट का वर्ष अनुसार आधार पर सभी पंजीकृत वि०वाच० छात्रों की सूची अनुरक्षित रखेगा। इस सूची में पंजीकृत छात्र का नाम, उसके शोध का क्षेत्र (विषय), उसके पर्यवेक्षक/उप पर्यवेक्षक का नाम, नामांकन/पंजीकरण की तिथि, सम्मिलित होंगे।

#### 4•0 विद्या वाचस्पति कार्यक्रम की अवधि (पंजीकरण कालावधि)

4•1 विद्या वाच० कार्यक्रम, पाठ्यक्रम कार्य सहित न्यूनतम तीन (3) वर्ष की अवधि का होगा और विद्या वाच० कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम छः (6) वर्ष का होगा।

4•2 अधिकतम दो (2) अतिरिक्त वर्ष पुनःपंजीकरण प्रक्रिया के माधम से दिये जा सकेंगे, जिसके लिये संबंधित स्कूल शोध समिति से विस्तार संबंधी स्वीकृति तथा विद्या वाच० कार्यक्रम में शोध-छात्रों के प्रवेश के समय लागू शुल्क के भुगतान एवं पुनःपंजीकरण शुल्क के रूप में रूपय 1,000/- का भुगतान आवश्यक होगा। इस विस्तार की स्वीकृति, शोध छात्र द्वारा लिखित आवेदन पर संबंधित स्कूल शोध समिति द्वारा, शोध परामर्शी समिति (शोध परा०समि० का गठन इस अध्यादेश के खण्ड 8•1 के अनुसार किया जायेगा) की संस्तुति पर प्रदान की जायेगी। शोध छात्र द्वारा विस्तार के अनुरोध में, अपेक्षित विस्तार के मूल में कारण को विनिर्दिष्ट करना होगा जिसकी संस्तुति स्कूल शोध समिति के विचारार्थ पर्यवेक्षक द्वारा की जायेगी। स्कूल शोध समिति लिखित में अभिलेखित कारणों सहित विस्तार प्रकरण पर विचार कर सकती है और विस्तार को स्वीकृति दे सकती है। तथापि, शर्त यह भी है कि विद्या वाच० कार्यक्रम पूरा करने के लिये सकल अवधि, विद्या वाच० कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अगले आठ (8) वर्षों से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती है।

4•3 महिला शोध छात्रों तथा निःशक्त व्यक्तियों (40 % से अधिक निःशक्तता धारियों) को दो (2) वर्षों की अतिरिक्त छूट अनुमत होगी। यह विस्तार, शोध छात्र द्वारा लिखित में अनुरोध किये जाने तथा शोध परामर्शी समिति की संस्तुति पर संबंधित स्कूल की स्कू०शो०समि० द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। तथापि, विद्या वाच० कार्यक्रम में प्रवेश पाने की तिथि से अगले दस (10) वर्षों से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती।

4•4 महिला शोध छात्राओं को, विद्या वाच० कार्यक्रम की समूची अवधि में मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल छुट्टी केवल 240 दिन के लिये ही सुलभ करायी जा सकती हैं और इस अवधि को पंजीकरण अवधि की गणना के रूप में गिना जायेगा।

4•5 यदि कोई शोध छात्र/छात्रा अपने शोध प्रबंध को अनुबंधित समय-सीमा में जमा नहीं करा पाता/पाती है तो उसका पंजीकरण/प्रवेश रद्द हो जायेगा।

#### 4•6 पूर्णकालिक शोध छात्रों के लिये अवकाश/अनुपस्थिति

4•6•1 प्रत्येक पंजीकृत शोध छात्र/छात्रा अपने पर्यवेक्षक के पास दैनंदिन आधार पर उपस्थित होगा/होगी जिससे कि वह निर्णय ले सके कि शोध छात्र/छात्रा को स्कूल/विश्वविद्यालय के अंदर अथवा बाहर कार्य करना है या फिर आवश्यकतानुसार बाह्य स्थान पर ही क्षेत्र कार्य निपटाना है। इस प्रकार की अनुपस्थिति अवधि, जिसमें 'संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों/परिसंवादों में भागीदारी भी सम्मिलित है, को 'काम पर' माना जायेगा न कि अवकाश पर/तथापि, किसी शिक्षण वर्ष में, एक बार ही में, एक मास से अधिक अवधियों के लिये विश्वविद्यालय से बाहर 'काम पर' शोध के लिये पर्यवेक्षक से लिखित

में पूर्व संस्तुति, शोध परामर्श का अनुमोदन तथा स्कूल अधिष्ठाता को विधिवत् सूचना, जिसका कि स्कूल शोध समिति की आगामी बैठक में अनुसमर्थन होना है, अपेक्षित होंगे।

4.6.2 विश्वविद्यालय से बाहर विद्या वाचक के काम पर शोध कार्य के समूचे कार्यकाल की अवधि, सामान्यतः क्षेत्र कार्य के लिये 24 मास की अवधि के लिये तथा सह पर्यवेक्षक के संस्थान में अथवा शोध परामर्श द्वारा नियत किसी अन्य स्थल पर कार्य के लिये 12 मास की अवधि के लिये सीमित होगी। किसी अन्य भावी विस्तार पर शोध परामर्श की संस्तुति (विस्तार हेतु औचित्य के साथ) पर स्कूल शोध समिति के अनुमोदन पर विचार किया जा सकता है।

4.6.3 पर्यवेक्षक, अध्येतावृत्ति-निधीयन-अभिकरण अथवा विश्वविद्यालय द्वारा (एक कलेंडर वर्ष में 30 दिन) जैसा भी अनुप्रयोज्य हो, परिभाषितानुसार शोध छात्र के लिये देय कुल अवकाशों में से, एक बार में पाँच (5) कार्य दिवसों से अधिक के अवकाश स्वीकृत नहीं कर सकते। पाँच (5) कार्य दिवसों से परे किसी अन्य अवकाश के लिये, शोध छात्र द्वारा पूर्व लिखित आवेदन पत्र, पर्यवेक्षक द्वारा अनुमोदन हेतु स्कूल अधिष्ठाता (डीन) को विधिवत् अग्रप्रेषण/संस्तुति हेतु अपेक्षित होंगे। ऐसे सभी मामले बाद में, शोध परामर्श एवं स्कूल शोध समिति को रिपोर्टित किये जायेंगे। अवकाश अवधि की इस अध्यादेश में अनुबंधितानुसार शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिये अपेक्षित कुल अवधि में, गणना की जायेगी।

4.6.4 पर्यवेक्षक, शोध छात्रों की रूग्णावस्था, मातृत्व अवकाश अथवा किसी अन्य कारणों से, शोध कार्य से अनुपस्थिति की रिपोर्ट शोध परामर्श और स्कूल-डीन के माध्यम से स्कूल शोध समिति को करेंगे। शोध कार्य की उपेक्षा और अनुशासन हीनता के मामले, जिनमें अनैतिक आचरण यथा अनधिकृत अनुपस्थिति, भावहरण (साहित्यिक चोरी), आंकड़ों का अयथार्थ निरूपण तथा अनियमितता को पर्यवेक्षक द्वारा रिकॉर्डित किया जाना चाहिये और शोध परामर्श को भेज दिया जाना चाहिये। शोध परामर्श उस पर मंथन करेगी और स्कूल शोध समिति को उसके विचारार्थ उपयुक्त संस्तुति करके भेज देगी। स्कूल शोध समिति शोध परामर्श को उसके विचारार्थ उपयुक्त संस्तुति करके भेज देगी। स्कूल शोध समिति, शोध परामर्श की संस्तुतियों और अन्य संबंधित तथ्यों पर विचार करेगी, उपयुक्त कार्यवाही, जिसमें उनके प्रवेश का रद्दीकरण भी सम्मिलित है, कर सकती है। तथापि, शोध छात्रों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जायेगा।

4.6.5 शोध छात्रों के सभी अवकाश रिकॉर्ड संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा अनुरक्षित किये जायेंगे।

#### 4.7 पंजीकरण का रद्दकरण/समाप्ति

4.7.1 किसी भी शोध छात्र के पंजीकरण का रद्दकरण/समाप्ति निम्न परिस्थितियों में हो सकता है:

- (i) यदि वह पूर्णकालिक शोध छात्रों के लिये लागू पर्यवेक्षक की अनुशंसा के पूर्व सूचना/स्वीकृति के बिना निरंतर दो सप्ताह की अवधि तक अनुपस्थित रहता है/रहती है।
- (ii) यदि वह विद्या वाचस्पति कार्यक्रम का त्याग कर देता/देती है और उस त्याग पत्र को पर्यवेक्षक द्वारा विधिवत् संस्तुत किये जाने के बाद स्कूल शोध समिति द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है।
- (iii) यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि में अपेक्षित शुल्क का भुगतान न करके अपने पंजीकरण का नवीनीकरण करने में सफल नहीं रहता/रहती है।
- (iv) यदि वह कदाचार और/अथवा अनुशासन हीनता के किसी भी कृत्य में संलिप्त पाया जाता/जाती है और उसके समापन को शोध परामर्श ने संस्तुत कर दिया है तथा स्कूल शोध समिति अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत किसी अन्य निकाय/सांविधिक अधिकारी ने अनुमोदित कर दिया है।
- (v) यदि वह इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में असफल रहता/रहती है।
- (vi) यदि वह निम्न खण्ड 8 में व्याख्यानानुसार दूसरी चेतावनी के उपरांत भी अपनी शोध-प्रगति, शोध परामर्श के संतुष्टि स्तर तक, कर पाने में असफल रहता/रहती है।

- (vii) यदि वह अनुबंधित समय सीमा में उपाधि (डिग्री) प्रदान किये जाने से जुड़ी अपेक्षाएँ पूर्ण करने में असफल रहता/रहती है।
- (viii) यदि वह शोध परामर्शी समिति को निरंतर दो छमाही रिपोर्ट देने में असफल रहता/रहती है।
- (ix) इस अध्यादेश में अन्यत्र विनिर्दिष्ट खंडों के अनुसार।

4.7.2 उपरोक्त 4.7.1 में सांराशितानुसार किसी भी कारण शोध छात्र के समापन आदेश, शोध परामर्श समिति द्वारा संस्तुति किये जायेंगे और संबंधित स्कूल शोध समि० द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे। ये आदेश संबंधित स्कूल-अधिष्ठाता (डीन) द्वारा जारी किये जायेंगे और अभिलेख उद्देश्य से अनु० तथा वि० प्र० को अग्रेषित कर दिये जायेंगे।

5.0 शोध पर्यवेक्षक: पर्यवेक्षक सह-पर्यवेक्षक होने के लिये पात्रता मापदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक विद्या वाचस्पति शोध छात्रों की अनुमेय संख्या आदि

5.1 ऐसे स्थायी शिक्षण सदस्य जो विद्या वाचस्पति उपाधि वाले संबद्ध महाविद्यालय/वि०वि०अध्य०स्कूल में आचार्य/सह-आचार्य के रूप में कार्यरत हों, तथा समकक्षी समीक्षा पत्रिका अथवा उल्लेखनीय पत्रिका (जर्नल) में कम से कम पाँच शोध प्रख्यापन (रिसर्च पब्लिकेशन) धारी हों और वि०वि०अध्य० विद्या वाचस्पति वाले संबद्ध महाविद्यालय में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत स्थायी शिक्षण सदस्य हों तथा समकक्षी समीक्षा पत्रिका अथवा उल्लेखनीय पत्रिका में कम से कम तीन शोध प्रख्यापन धारी हों तो उन्हें ही उस विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता मिलेगी जहाँ पर शिक्षण सदस्य नियोजित है अथवा इसके संबद्ध स्नातकोत्तर। ऐसे मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक उन अन्य संस्थानों में, जहाँ वे केवल सह पर्यवेक्षक के रूप में ही कार्य कर सकते हैं, शोध छात्रों का पर्यवेक्षक नहीं कर सकते। सहायक शिक्षण सदस्य शोध पर्यवेक्षक के रूप में ही कार्य कर सकते हैं, शोध छात्रों का पर्यवेक्षण नहीं कर सकते। सहायक शिक्षण सदस्य शोध पर्यवेक्षक के रूप में कार्य नहीं कर पायेंगे बल्कि वे केवल सह-पर्यवेक्षक के रूप में ही कार्य कर पायेंगे।

तथापि, कार्य चिकित्सा एवं पराचिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्कूल में, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के मान्यता प्राप्त ऐसे शिक्षक जिनके पास एम डी/एम एस/डीएम/एम सी एच अथवासमतुल्य डिग्री (परन्तु, विद्यावाचस्पति की डिग्री नहीं) है और एम डी/एम एस/डीएम/एम सी एच डिग्री अथवा समतुल्य डिग्री प्राप्ति के पश्चात् 15 वर्षों का शिक्षण एवं शोध अनुभव है, जिसमें फ़ैकल्टी सदस्य के रूप स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने का 10 वर्ष का अनुभव सम्मिलित हैं; सूचक समकक्षी समीक्षा पत्रिका में 10 शोध लेख प्रकाशित हो चुके हैं और सतत रूप से शोध गतिविधियों में अभी भी संक्षिप्त हैं, विद्या वाचस्पति पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों को भी पूरा करते होंगे।

5.2 एक मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक, किसी शोध छात्र का एकल पर्यवेक्षक बना रह सकता है यदि पर्यवेक्षक की अधिवर्षता अवधि 03 वर्ष शेष रह गयी है। अधिवर्षता तक सेवा के अंतिम 3 वर्षों की अवधि के लिये, पर्याप्त सेवा अवधि धारी एक अतिरिक्त मान्यता प्राप्त सह पर्यवेक्षक की आवश्यकता होगी इसलिये संबंधित स्कूल शोध समिति द्वारा एक सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जायेगी। तथापि, यदि शोध प्रबन्ध जमा करा दिया गया है परन्तु मौखिक परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है या फिर डिग्री प्रदान नहीं की गयी है तो फिर सह-पर्यवेक्षक की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, यदि बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् शोध प्रबंध लौटा दिया जाता है तो स्कूल शोध समि० सह पर्यवेक्षक/अभीक्षक पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर सकती है अधिवर्षता से पूर्व, तीन वर्ष की सेवावधि से कम वाले शिक्षण सदस्यों को अपने पर्यवेक्षण के अधीन नये शोध छात्र लेने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, ऐसे शिक्षण सदस्य अधिवर्षता तक, पहले से ही पंजीकृत विद्या वाचस्पति शोध छात्रों के पर्यवेक्षण को जारी रखने और अधिवर्षता के पश्चात्, लेकिन 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व सह पर्यवेक्षक के रूप में नये शोध छात्र को अपने पर्यवेक्षण में जारी रखे रहने की अनुमति होगी।

- 5•3 सह पर्यवेक्षक(ि) को अन्य विश्वविद्यालय स्कूलों/विश्वविद्यालयी केन्द्रों/सम्बद्ध महाविद्यालयों/अन्य केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से अन्तर-विषय क्षेत्रों में अनुमति होगी बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति इस अध्यादेश के अनुसार पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिये शैक्षिक अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों। सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति के लिये नियम एवं शर्तें, शोध परामर्शी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेंगी तथा सह-पर्यवेक्षक को संकाय के केन्द्र मूल स्कूल की संबंधित स्कूल शोध समि० शोध समि० तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। उसकी सूचना अनु० तथा वि० प्रको० को दी जायेगी।
- 5•4 पर्यवेक्षक को एक से अधिक विषयों के लिये मान्यता दी जा सकेगी, एक मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक, इस तथ्य का ध्यान किये बिना कि वह विद्या-वाचस्पति कार्यक्रम प्रस्तावित किये जाने के लिये अनुमत वि० वि० अध्य० स्कूल संबद्ध महाविद्यालय से संबंधित है, उस विषय की संचालक स्कूल शोध समित० का सदस्य हो जायेगा। वि०वि० अध्य० स्क० के एक संकाय सदस्य को, उसके मूल स्कूल/केन्द्र की स्कूल शोध समि० की स्वीकृति से और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से विभिन्न वि०वि० अध्य० स्कूल/केन्द्र में पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दे दी जायेगी। संबंधित शिक्षक के पास अध्यापन और शोध संबंधी सभी दायित्व उन सभी स्कूलों/केन्द्रों में होंगे जहाँ वह मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक होगा।
- 5•5 कोई भी शोध पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक, जो आचार्य (प्रोफेसर) रहे हैं, किसी भी समय पर, आठ (08) से अधिक विद्या वाचस्पति छात्रों का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। किसी शोध पर्यवेक्षक के रूप में एक सह-आचार्य अधिकतम छः (06) विद्या वाच० शोध छात्रों का मार्ग दर्शन कर सकते हैं। सहायक आचार्य, शोध पर्यवेक्षक के रूप में अधिकतम चार (04) विद्या वाच० शोध छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। संयुक्त पर्यवेक्षण के मामले में, नामांकित शोध छात्रों की संख्या प्रति एक संयुक्त पर्यवेक्षण के मामले में, नामांकित शोध छात्रों की संख्या प्रति एक संयुक्त पर्यवेक्षक के लिये एक विद्या वाच० शोध छात्र ही होगी।
- 5•6 यदि एक सह-पर्यवेक्षक का आबंटन इस विश्वविद्यालय (अथवा इसके सम्बद्ध महाविद्यालय) से किया जाता है, और यदि वि०वि०अध्य० स्कूल/केन्द्र का शिक्षक अपने मूल वि०वि०अध्य०स्कूल/केन्द्र के साथ-साथ किसी अन्य वि०वि०अध्य०स्कूल/केन्द्र अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान में पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक के रूप में अंतर्निहित है तो अनिवार्य हो जाता है कि वह स्कूल शोध समिति को ऐसे शोध छात्रों की संख्या के विषय में सूचित करे जिससे कि इस अध्यादेश के अनुसार विद्या वाचस्पति के लिये अनुमेय/उपलब्ध स्थानों की गणना में उनकी भी गिनती की जा सके। संबंधित स्कूल शोध समिति को इस की सूचना देने में रही विफलता को कदाचार के रूप में समझा जायेगा, जिसके लिये उपयुक्त कार्रवाई संस्तुत की जायेगी। जैसे ही, कोई पंजीकृत शोध छात्र मूल्यांकन के उद्देश्य से अपना शोध-प्रबंध जमा करा देता है तो उसका विद्या वाचस्पति स्थान/सीट की गणना उस मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक के पक्ष में रिक्त समझा जायेगा। यह शोध प्रबंध, विद्या-वाचस्पति शोध छात्र द्वारा जमा किये जाने की पूर्व प्रस्तुति के बाद संबंधित स्कूल/केन्द्र के निदेशक/डीन के कार्यालय में, मूल्यांकन उद्देश्य के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।
- 5•7 एक पूर्णकालिक नियमित शिक्षक, पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिये, अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति कर देने की स्थिति में, संबंधित स्कूल शोध समि० को आवेदन करेंगे। अनु० तथा वि० प्रको० निदेशक, स्कूल शोध स० की संस्तुति पर और कुलपति से अनुमोदन प्राप्त कर लेने के पश्चात् शिक्षक की पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता के संबंध में अधिसूचना जारी करेंगे। ऐसी मान्यता के लिये प्रपत्र अनु० तथा वि० प्रको० द्वारा विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षकों की सूची अनु० तथा वि० प्रको० द्वारा विश्वविद्यालय वैबसाइट पर प्रदर्श की जायेगी।
- 5•8 ऐसे मामलों/मामलों में, जहाँ कोई पर्यवेक्षक सेवानिवृत्ति हो जाता है, त्याग पत्र दे देता है, एक वर्ष से अधिक के लिये अवकाश/प्रतिनियुक्ति पर चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अथवा किसी अन्य अज्ञात परिस्थितिवश शोध छात्र का [पुनर्वितरण/पुनर्आवंटन](#) अनिवार्य हो जाता है तो स्कूल शोध

समि० आदर्श रूप से उसी स्कूल/संस्थान/विषय में से अधिकसंख्यक आवंटन के रूप में पर्यवेक्षक(ी)/सह-पर्यवेक्षक(ी)/प्रभारी पर्यवेक्षक(ी) का आवंटन करेंगे और अनु० तथा वि० प्रको० को सूचित करेंगे। ऐसे मामले/मामलों में जहाँ स्कूल शोध समि० विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विषय के संबंध में पर्यवेक्षक को पहिचानने में असमर्थ रहती है तो पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त किये जा सकने हेतु अपेक्षित शिक्षण मापदण्डों पर खरा उतरने वाले किसी भी व्यक्ति के चयन के लिये छात्र अनुमत होगा लेकिन इसके लिये अनु० तथा विकास प्रको० और कुलपति के माध्यम से स्कूल शोध समिति का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

5.9 ऐसे मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षकों, जिन्हे एक वर्ष (या अधिक) के लिये दीर्घ अवकाश/प्रतिनियुक्ति/धारणाधिकार (लियन) (विद्यवाचस्पति प्रवेश के लिये साक्षात्कार अथवा पर्यवेक्षक के आवंटन के समय) स्वीकृत कर दिये गये हैं अथवा वे अग्रसरित हो गये हैं, को उस शैक्षणिक सत्र में शोध छात्र आवंटित नहीं किये जायेंगे।

5.10 कोई भी शोध छात्र उपयुक्त औचित्य के साथ संबंधित स्कूल के अधिष्ठाता (डीन) के माध्यम से संबंधित स्कू०शो०समि० को पर्यवेक्षक(ी) को बदलने के लिये लिखित में आवेदन कर सकता है। इस प्रकार के आवेदन में दी गई परिस्थितियों पर विचार करने के बाद स्कूल शोध समि० सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अभिलेखन के लिये अनु० तथा वि० प्रको० को सूचित करते हुए पर्यवेक्षक(ी) के बदलाव के आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं।

5.11 विवाह अथवा किसी अन्यथा कारण से महिला विद्या वाचस्पति शोधकर्ता के पुनःस्थानन के मामले में, शोध आधार सामग्री उस विश्वविद्यालय जिसमें शोधकर्ता पुनःस्थानन होने की इच्छुक है, को अंतरित करने के लिये अनुमत कर दिया जायेगा बशर्ते कि इन विनियमों की अन्य शर्तों का पालन किया गया हो तथा शोध कार्य निधियन अभिकरण द्वारा मूल संस्थान/पर्यवेक्षक को अभिस्वीकृत, किसी परियोजना से संबंधित न हो। ऐसे में, इस प्रकार की शोधकर्ता पहले से ही संपादित शोध के भाग का श्रेय मूल संस्थान तथा पर्यवेक्षक को देगी।

## 6.0 विद्यावाचस्पति कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का प्रवेश

6.1 प्रत्येक पर्यवेक्षक, उपरोक्त 5.5 खंड में विनिर्दिष्टानुसार विद्या वाचस्पति शोध छात्रों की अनुमत संख्या से कुल मिलाकर, अधिसंख्य आधार पर केवल दो, अंतरराष्ट्रीय छात्रों का मार्गदर्शन कर सकता है।

6.2 अंतरराष्ट्रीय छात्रों के विद्या वाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेश की कार्यविधि निदेशक अनु० तथा वि० प्रको० और कुलपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय मामले के निदेशालय द्वारा पृथकतः अधिसूचित किया जायेगा। विस्तृत प्रक्रिया इस अध्यादेश के आनुरूप्य में अंतरराष्ट्रीय मामले निदेशालय द्वारा प्रस्तावित की जायेगी तथा विद्वत् परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् विनियम के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।

6.3 किसी भी समय में, विद्यावाचस्पति छात्रों की कुल संख्या, पर्यवेक्षक अथवा सह पर्यवेक्षक के रूप में शिक्षण सदस्य के अंतर्गत उपरोक्त खण्ड 5.5 एवं खण्ड 6.1 में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी।

7.0 पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) : क्रेडिट अपेक्षाएँ, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम, पूर्णता के लिये न्यूनतम मानक आदि।

7.1 विद्या वाचस्पति पाठ्यक्रम कार्य के लिये क्रेडिट अपेक्षाएँ, वर्ष 2019 में डी०ओ०सं० एफ 1-1/2018 (जनरल/सीएआरई के द्वारा वि०अनु० आयोग द्वारा अधिसूचितानुसार "शोध एवं प्रकाशन आधारनीति" पाठ्यक्रम तथा शोध कार्य प्रणाली पाठ्यक्रम सहित कम से कम 12 क्रेडिट्स होंगी। शोध परामर्श समिति, विद्या वाचस्पति कार्यक्रम के जिसे क्रेडिट अपेक्षाओं के भाग के रूप में वि०वि०अनु० आयोग से मान्यता प्राप्त ऑन लाइन पाठ्यक्रमों की संस्तुति कर सकती है।

- 7•2 पाठ्यक्रम कार्य का अनुदेशन माध्यम अंग्रेजी होगा जब तक कि विनिर्दिष्ट संरूप और अनुदेशानुसार, प्रवेश/पंजीकरण के समय संबंधित स्कूल शोध समि० द्वारा लिखित में अभिलिखित कारणों के आधार पर अन्यथा अनुमोदन न किया गया हो।
- 7•3 विद्यावाचस्पति के लिये विस्तृत पाठ्यक्रम कार्य का अभिकल्पन एवं अनुशंसा संबंधित स्कूल शोध समि० द्वारा किये जायेंगे एवं अनुमोदन संबंधित पाठ्य समिति और विद्वत परिषद् द्वारा किया जायेगा।
- 7•4 विद्यावाचस्पति पाठ्यक्रम कार्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम क्रेडिट समय अनुदेशीय अपेक्षाओं की पुष्टि के अनुसार होगा तथा विषय सामग्री, अनुदेशीय एवं मूल्यांकन विधियों को विनिर्दिष्ट करेगा।
- 7•5 उस विषय को, संचालित करने वाली स्कूल शोध समि०, जिसमें शोधार्थी अपना शोध कार्य कर रहा है/रही है, शोध छात्रों के लिये शोध परामर्शी समिति की अनुशंसाओं पर आधारित निर्धारित पाठ्यक्रम(ों) को विहित करेगी। सभी शोध छात्रों से विषय की चिंता किये बिना, अपेक्षा की जायेगी कि उन्हीं अपनी आचार्यत्व शोध अवधि में विद्या वाचस्पति हेतु चयनित विषय से संबंधित शिक्षण/शिक्षा/अध्यापन/लेखन का प्रशिक्षण दिया जाये। विद्या वाचस्पति शोधार्थियों को शिक्षकीय अथवा प्रयोगशाला कार्य एवं मूल्यांकन करने हेतु शिक्षण/शोध सहायकत्व के लिये प्रति सप्ताह 4-6 घंटे भी नियत किये जा सकेंगे।
- 7•6 विद्यावाचस्पति कार्यक्रम(ों) में प्रवेश प्राप्त सभी छात्रों के लिये यह अपेक्षित होगा कि वे स्कूल शोध समिति द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम कार्य को प्रारम्भिक एक या दो सत्रक में पूर्ण कर लें। पाठ्यक्रम कार्य के पूर्ण करने की अधिकतम अवधि शोधार्थी के प्रवेश के शिक्षण सत्र से दो वर्ष की होगी। यदि शोधार्थी किसी विषय/परीक्षा पत्र में असफल हो जाता है तो शोधार्थी बाद के लिये अनुसूचित विषय/परीक्षा पत्र की परीक्षा में पुनर्सम्मिलित होगा।
- 7•7 जिस अभ्यर्थी के पास पहले से ही एम० फिल० की डिग्री है और उसने विद्यावाचस्पति कार्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो उसे वि०वाच० पाठ्यक्रम कार्य से स्कूल शोध समि० द्वारा छूट दे दी जायेगी। वि० वाच० कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अन्य सभी अभ्यर्थियों को स्कूल शोध स० द्वारा निर्धारित वि० वा० पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करना होगा। पहले से ही पाठ्यक्रम पूर्ण किये हुए और वि० वाच० कार्यक्रम के पाठ्यक्रम कार्य से छूट चाहने वाले शोधार्थी को इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम कार्य के दिशानिर्देशों के अनुरूप में होना चाहिये। वि०वाच० पाठ्यक्रम कार्य से अभ्यर्थी को दी गयी छूट को छात्र के प्रवेश के प्रथमवर्ष में स्कूल शोध स० द्वारा लिखित में प्रलेखित किया जायेगा।
- 7•8 पाठ्यक्रम कार्य के लिये श्रेणी कारण प्रणाली एवं परीक्षा श्रेणियाँ विश्वविद्यालय के अध्यादेश -11 में विनिर्दिष्टानुसार ही होंगी। पाठ्यक्रम कार्य का प्रत्येक प्रश्न पत्र/विषय अधिकतम 100 अंकों का होगा। शिक्षक के सतत मूल्यांकन घटक 25 अंकों के होंगे तथा अन्त अवधि सत्रक परीक्षा घटक 75 अंकों का होगा।
- 7•9 पाठ्यक्रम कार्य में उपस्थिति की अपेक्षा कुल आयोजित कक्षाओं की 75% होगी/स्कूल शोध स० विशिष्ट मामलों में, लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए उपस्थिति में 5% की अनदेखी कर सकती हैं। किसी भी परिस्थिति में, पाठ्यक्रम में 70% से कम उपस्थिति धारक शोधार्थी को स्कूल शोध स० द्वारा सत्रावधि सत्रक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। निरुद्ध (परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं हो पायेगी) शोधार्थियों की सूची स्कूल शोध स० के अध्यक्ष द्वारा सत्रांत अवधि परीक्षा के प्रारम्भ होने से कम से कम पाँच कार्य दिवस पूर्व अधिसूचित की जायेगी जिसकी एक प्रति परीक्षा नियंत्रक को, प्रवेश पत्र जारी न किये जाने के आशय से, प्रेषित की जायेगी।
- 7•10 प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये 25 अंकों का शिक्षक द्वारा सतत मूल्यांकन, उस संबंधित शिक्षक द्वारा किया जायेगा जिस को स्कूल शोध समि० द्वारा पाठ्यक्रम पढ़ाने का दायित्व सौंपा गया था। संबंधित शिक्षक

सत्र समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर अधिष्ठाता के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को अंक सूची प्रेषित करेंगे।

शेष 75 अंकों के लिये परीक्षा नियंत्रक परीक्षा का आयोजन करेंगे। पाठ्यक्रम समि० द्वारा यथा स्वीकृत, प्राशिनकों की सूची परीक्षा नियंत्रक का सूचित कर दी जायेगी। परीक्षा नियंत्रक, शिक्षकों द्वारा सतत मूल्यांकन एवं अन्तिम अवधि सत्रक परीक्षा को एक जुट करते हुए, परिणाम घोषित कर देंगे। सत्रक की अवधि 15 सप्ताह की होगी। किसी भी प्रश्न पत्र/पाठ्यक्रम हेतु परीक्षा की अन्य विधि अनुमत नहीं होगी।

- 7•11 किसी भी विद्यावाच० शोधार्थी को, कार्यक्रम में बने रहले और अपना शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत कर पाने की पात्रता प्राप्त करने के लिये पाठ्यक्रम कार्य में वि०वि०अनु०आयोग के 10 बिन्दु मापक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। यदि शोधकर्त्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त नहीं कर पाता/पाती तो शोधकर्त्ता को अपनी श्रेणी में सुधार लाने के लिये किसी एक या अधिक पाठ्यक्रम कार्य प्रश्नपत्र/पाठ्यक्रम(ि) में पुनः सम्मिलित होना होगा। अनुप्रयोज्य पुनः प्रवेश शुल्क, विश्वविद्यालय की अन्य परीक्षाओं के लिये अधिसूचित शुल्क के समरूप ही होगा। यदि, विनिर्दिष्टानुसार पाठ्यक्रम-कार्य के लिये अधिकतम अवधि में, अपेक्षित न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न की जा सकी होगी तो शोधकर्त्ता का पंजीकरण/प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जायेगा। वि०वि०अध्य०स्कू०/केन्द्र के अधिष्ठाता/निदेशक, अभिलेखों के अद्यतन के लिये अनु० तथा वि०प्रकोष्ठ सूचित करेंगे।

## 8•0 शोध परामर्श समिति और इसके प्रकार्य

- 8•1 स्कूल में प्रविष्ट प्रत्येक शोधार्थी के लिये एक शोध परामर्श समिति (आर०ए०सी०) होगी। इस शो० प०स०(आर०ए०सी०) में न्यूनतम 5 सदस्य होंगे। इस शो०प०स० का संघटन निम्नानुसार होगा:

- (क) स्कूल के एक आचार्य जो स्कूल शोध समि० के भी सदस्य होंगे-अध्यक्ष
- (ख) शोधार्थी के पर्यवेक्षक के अतिरिक्त दो/तीन मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक प्राधिमानतः उसी स्कूल शोध समि० में पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त सदस्य
- (ग) शोधार्थी के सह पर्यवेक्षक (यदि होई हों तो)-सदस्य
- (घ) शोधार्थी के पर्यवेक्षक-संयोजक सदस्य

शो०परा०समि० के लिये सदस्यों का प्रस्ताव, सम्बन्धित वि०वि०अध्य०स्कूल/केन्द्र के स्कूल शोध समि० के विचारार्थ और अनुमोदन हेतु पर्यवेक्षक द्वारा ही प्रस्तावित किया जायेगा। विश्वविद्यालय के बाहर से बाह्य विषय विशेषज्ञ को भी, यदि आवश्यकता हो तो स्कूल शोध समि० के अनुमोदन से सहयोजित किया जा सकता है। शोधार्थी का शोध पर्यवेक्षक इस समिति का संयोजक होगा। इस समिति के निम्न दायित्व होंगे:

- 8•1•1 शोध प्रस्ताव का पुनर्विलोकन करना और शोध के विषय का निर्णय करना। शोधार्थी के शोधकार्य हेतु सार संक्षेप/रूप रेखा को, कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से विद्या वाच० कार्यक्रमों 12 मास के भीतर ही अंतिम रूप दे दिया जायेगा। निश्चित रूप में प्राप्त सार संक्षेप को अनुमोदन के लिये स्कूल शोध स० को अग्रेषित किया जायेगा और अभिलेखान के लिये अनु० तथा वि० प्रको० को भेज दिया जायेगा। रूप-रेखा के निर्धारित अवधि में अन अंतिमीकृत रह जाने की स्थिति में, शोधार्थी का प्रवेश रद्द हो जायेगा।

- 8•1•2 अध्ययन अभिकल्पन तथा शोध की कार्य प्रणाली को विकसित करने और उन पाठ्यक्रम(ि), जो उपरोक्त खण्ड 7 के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रमों में से उसे चुनना होगा, को पहचानने में शोध छात्र का मार्ग दर्शन करना।

- 8•1•3 शोध छात्र के शोध कार्य की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा और उसकी प्रगति में सहायता करना । शोध परा० स० द्वारा किये गये मूल्यांकन और संस्तुतियाँ आगामी आवश्यक कार्यवाई हेतु संबंधित स्कूल शोध समि० को प्रस्तुत किये जायेंगे ।
- 8•1•4 प्रत्येक शोध छात्र की वह अकादमिक शोध प्रगति, संबंधित शो०परा०समि० द्वारा प्रत्येक छमाही आधार पर अनुवीक्षित की जायेगी, जो शोध छात्र द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रति रिपोर्ट और मौखिक प्रस्तुतिकरण पर आधारित होगी । सही समय पर शो०परा०स० को प्रगति रिपोर्ट भेजने और/या प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करने में रही असफलता का अनुशासनहीनता के रूप में लिया जायेगा और तदनुसार ही व्यवहार किया जायेगा । शो० परा० समि० की बैठक के बाद उनके पर्यवेक्षकों द्वारा अग्रेषिता सभी पंजीकृत शोध छात्रों की प्रगति विवरणिका स्कूल शोध स० के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी शोध परा० समि० की इन टिप्पणियों के साथ कि क्या शोध छात्र की प्रगति अच्छी/ संतोषजनक/ स्तरहीन रही । प्रगति विवरणिका और शो० परा० समि० की टिप्पणी का विचार करने के बाद स्कूल शोध समि० निम्न में से कोई एक संस्तुति करेगी:
- (i) पंजीकरण की सततता
  - (ii) शोध छात्र को लिखित चेतावनी के साथ पंजीकरण की सततता; इसमें उसके निष्पादन में सुधार के लिये उठाये जाने वाले आवश्यक उन उपायों को सम्मिलित किया जायेगा जिन्हें वह अपने पर्यवेक्षक(ों) के साथ परामर्श से पहचान पायेगा । द्वितीय और अंतिम चेतावनी, उनके द्वारा शोध ग्रंथ जमा कराने हेतु पंजीकरण अवधि में न्यूनतम एक वर्ष का विस्तार बढ़ा देगी ।
  - (iii) पंजीकरण का रद्दकरण, यदि शोध छात्र द्वितीय और अंतिम चेतावनी दिये जाने के उपरांत भी शोध परा स० और स्कूल शोध स० के संतुष्टि स्तर तक प्रगति कर पाने में असफल रहे
- 8•2 एक शोध छात्र, प्रस्तुतिकरण देने और मूल्यांकन के लिये अपने कार्य की, प्रगति संबंधी एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने और भविष्य के लिये मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये छः मास में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होगी । छमाही प्रगति रिपोर्ट शोध परामर्श समिति संबंधित स्कूल शोध स० को भेजेगी और उसकी एक प्रति शोध छात्र को भी भेजी जायेगी । स्कूल शोध समि० स्कूल में पंजीकृत सभी शोधार्थियों की समेकित संक्षिप्त रिपोर्ट, अनु० तथा वि०प्र० को शोधार्थियों की प्रगति के संबंध में सूचनार्थ एवं अभिलेखन के लिये भेजेंगे । शोध सलाहकार समिति के संयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि शो०परा० की कम से कम एक बैठक प्रत्येक छः माह में संचालित की जायेगी ।
- 8•3 यदि शोध छात्र की प्रगति असंतोषजनक पायी जाती है तो शोध सलाहकार समिति उसके कारण अभिलिखित करेगी और सुधारात्मक उपाय सुझायेगी । यदि, शोधार्थी इन सुधारात्मक उपायों को अपनाने में असफल रहता है तो शोध परामर्श समिति, शोध छात्र के पंजीकरण को रद्द करने के लिये विशिष्ट कारण दर्शते हुए संबंधित स्कूल शोध समि० को संस्तुति कर सकती है ।
- 9•0 उपाधि (डिग्री) प्रदान किये जाने के लिये मूल्यांकन एवं निर्धारण विधियाँ, न्यूनतम मानक/क्रेडिट्स आदि
- 9•1 विद्या वाच० शोधार्थियों से अपेक्षा होगी कि वे विद्या वाच० कार्यक्रम की इस परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम में निर्धारितानुसार और इस अध्यादेश की आनुरूप्यता में शोधकार्य प्रारम्भ करें और युक्तियुक्त समय में शोध प्रारूप जमा करें, साथ ही उपरोक्त खण्ड-7 में निर्धारित अंक/ श्रेणी प्राप्त करते हुए पाठ्यक्रम कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करें ।
- 9•2 विद्या वाच० शोधार्थियों को न्याय निर्णयन हेतु शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व स्कोपस/ बैच ऑफ साइंस इन्डैक्सड जॉर्नल्स में कम से कम एक शोध पत्र प्रकाशित (अथवा शोधपत्र स्वीकृत) करा लेना चाहिये और उसके साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिये । तथापि, विज्ञान/ अभियंत्रण/ प्रौद्योगिकी/ प्रबंधन के अतिरिक्त स्कूलों/ विद्याओं के मामलों में, जहाँ कोई भी नहीं अथवा सीमित संख्या में स्कोपस/ बैच

ऑफ साइंस इन्डैक्स जॉर्नल्स उपलब्ध हैं तो संबंधित विद्याओं की स्कू0 शो0 स0 लिखित में अभिलिखित कारण देते हुए उक्त शर्तों में छूट दे सकती है। तथापि, ऐसे मामलों, में प्रकाशन कम से कम समकक्षी-समीक्षात्मक जॉर्नल्स (आई एस एस एन) में होना चाहिये। तथापि, संबंधित विद्याओं की स्कू0 शो0 स0, विद्या वाच0 कार्यक्रम के दौरान पेपर प्रकाशन हेतु उच्च कसौटी निर्धारित कर सकते हैं।

- 9.3 शोध कार्य समाप्त हो जाने के बाद, शोध छात्र अपने शोध ग्रन्थ के पूर्व-प्रस्तुति संक्षिप्त सार की 08 प्रतियाँ अपने पर्यवेक्षक के माध्यम से शोध परामर्श समिति वे प्रस्तुत करेगा तथा शोध परामर्श समिति के समक्ष पूर्व प्रस्तुत प्रदर्शन करेगा। यह पूर्व प्रस्तुति प्रदर्शन, सभी शिक्षण सदस्यों तथा विश्वविद्यालय के अन्य शोध-छात्रों के लियें भी प्रदर्शनीय होगा। उनसे प्राप्त प्रति पुष्टियाँ तथा टिप्पणियाँ शोध परामर्श समिति के परामर्श से शोध प्रारूप में उपयुक्त ढंग से समाविष्ट कर ली जायेंगी। पूर्व प्रस्तुति प्रदर्शन के बाद विद्यावाच0 शोध ग्रंथ की प्रस्तुति की अनुमति। अस्वीकृति का निर्णय सूचनार्थ, संबंधित स्कूल शोध समि0 के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- 9.4 शोध छात्र को, प्रस्तुति पूर्व प्रस्तुतिकरण की शोध परा0समि0 द्वारा अनुमोदन की तिथि से तीन माह के भीतर अपना शोध पत्र जमा करना होगा। तथापि, यदि शोध छात्र अनुबंधित समय सीमावधि में अपना शोध पत्र जमा कराने में असफल रहता/रहती है और इसके लिये उसके पास उपयुक्त कारण भी है तो स्कूल शोध समि0 (अथवा एस आर सी के अनुमोदन की शर्त पर, जो भी उपयुक्त हो) की अनुशंसा पर स्कूल के डीन अधिकतम तीन माह के विस्तार की स्वीकृति दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रस्तुति पूर्व प्रस्तुतिकरण के शो0 परा0 स0 द्वारा अनुमोदन तिथि से 06 माह के भीतर शोध छात्र को अपना शोध ग्रन्थ जमा करवाने की अनुमति होगी। यदि कोई शोध छात्र, प्रस्तुति पूर्व प्रस्तुतिकरण तिथि से 06 मास के भीतर अपना शोध-ग्रंथ जमा करवाने में असफल रहता/रहती है तो उसे शोध परा0 समि0 के समक्ष नये सिरे से प्रस्तुतिकरण करना होगा।
- 9.5 शोध का अंतिम शीर्ष, शोध परा0 स0 द्वारा छात्र के प्रस्तुति पूर्व प्रस्तुतिकरण के समय अनुमोदित किया जायेगा।
- 9.6 शोधग्रन्थ अंग्रेजी में ही लिखे जायेंगे जब तक कि अन्यथावस्था के लिये संबंधित शोध परा0 समि0 द्वारा लिखित में कारणों को अनुमोदित न किया गया हो साथ ही विनिर्दिष्ट संरूप और अनुदेशों के अनुसार प्रवेश/पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर स्कूल शो0स0 द्वारा अनुमोदित न किया गया हो। शोधपत्र का संरूप कुलपति की स्वीकृति से अनु0 तथा विका0 पु0 द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- 9.7 सभी शोध छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शोध कार्य में नैतिक व्यवहार का पालन करेंगे। शोध कार्य में भावहरण (साहित्य चोरी) तथा अन्य प्रकार के शैक्षणिक कपट (बेईमानी) निवारण के लिये सभी शोध छात्र एवं पर्यवेक्षक विश्व विद्यालय की वेबसाइट (<http://www/ipu/ac.in@pubinfo2020@nt655210820.pdf>) पर उपलब्ध "जी जी एस आई पी यू शैक्षणिक शोध एवं नैतिक व्यवहार विनियम 2022" शीर्ष से दिये गये विश्वविद्यालय विनियमों का पालन करेंगे।
- 9.8 एक विद्या वाचस्पति शोध छात्र मूल्यांकन के लिये अपना शोध प्रबंध (क) विद्या वाचस्पति शोध छात्र द्वारा इस आशय के एक वचन बंध कि इसमें कोई भी भावहरण सम्मिलित नहीं हैं (ख) शोध प्रबंध की मौलिकता का सत्यापन करने वाले, शोध पर्यवेक्षक द्वारा प्रदत्त, प्रमाण पत्र जिसमें यह भी उल्लिखित हो कि यह शोध प्रबन्ध इस विश्वविद्यालय अर्थात् किसी अन्य संस्थान को कोई भी अन्य उपाधि (डिग्री)/डिप्लोमा प्रदान किये जाने के उद्देश्य प्रस्तुत नहीं किया गया है के साथ जमा करायेगा।
- 9.9 शोध छात्र द्वारा प्रस्तुत विद्या वास्पति शोध प्रबंध का मूल्यांकन उनके शोध पर्यवेक्षक द्वारा और कम से कम दो उन बाह्य परीक्षकों, जो अपने विषय क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे और विश्वविद्यालय तथा इसके सम्बद्ध किसी अन्य संस्थान के नियोजन में नहीं होंगे, के द्वारा किया जायेगा। ऐसे परीक्षकों को अपने

क्षेत्र में शोध प्रकाशन के अच्छे रिकॉर्ड के साथ एक अकादमियन होना चाहिये। मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गयी समीक्षाओं और अन्य दूसरी बातों पर आधारित 'मौखिक परीक्षा' का संचालन नीचे दिये गये खण्ड 9.12.2 में विवरणानुसार 'मौखिक प्रतिवाद समिति' द्वारा किया जायेगा तथा यह शोध सलाहकार समिति के सदस्यों, स्कूल के सभी शिक्षण सदस्यों, विश्वविद्यालय के सभी मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षकों, अन्य शोध छात्रों तथा अन्य इच्छुक विशेषज्ञों/शोधकर्ताओं और अन्य छात्रों द्वारा भाग लिये जाने के लिये खुली होगी।

### 9.10 विद्या वाचस्पति शोध प्रबंध हेतु परीक्षकों की नियुक्ति

9.10.1 विद्या वाचस्पति शोध प्रबंध के मूल्यांकन के उद्देश्य से संबंधित वि०वि० अध्या० स्कूल/केन्द्र के मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक, शोध कार्य के विषय क्षेत्र से कम से कम 8-10 विशेषज्ञों, की सूची प्रस्तुत करें, जो कि सह-आचार्य के पद से नीचे के न हों और इसमें भी संबंधित विषय (विद्या) के स्कूल शो०स० के अनुमोदन के लिये 4-5 विशेषज्ञ राज्य/देश से बाहर के हों। इन विशेषज्ञों के पास गु०गो०सि०इ०प्र० विश्वविद्यालय में पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्ति हेतु अपेक्षित तुल्य अर्हता होनी चाहिये। इन्हें वि०वि०अनु०आयोग से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय में विद्या वाचस्पति के रूप में जाना जाता हो अथवा सरकार द्वारा स्थापित किसी राष्ट्रीय शोध एवं तकनीक संस्थान में सेवारत हैं। अथवा सेवा निवृत्त हों। एक संस्थान से केवल एक परीक्षक ही उपलब्ध हो सकेगा। स्कू०शोध समि० पर्यवेक्षक(ि) द्वारा प्रस्तावित किसी भी नाम को जोड़ सकती है या काट सकती है। प्रत्येक परीक्षक(ि) से संबंधित पूर्ण संपर्क विवरण, पत्राचार पता इमेल, दूरभाष/चलभाष, फ़ैक्स आदि उपलब्ध कराने का दायित्व पर्यवेक्षक का होगा।

9.10.2 कोई भी परीक्षक न तो उस संस्थान से संबंधित हो सकता है जिससे शोध छात्र जुड़ा हुआ है और नही उस संस्थान से, जिसमें शोध छात्र के पर्यवेक्षक अथवा सह-पर्यवेक्षक नियोजित हैं। साथ ही, शोध छात्र के सहयोगी अथवा सहलेखक या संबंधित विद्या वाचस्पति के शोध कार्य काल में रहे उसका पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक एक परीक्षक नहीं हो सकता। यह सुनिश्चित करने का दायित्व शोधकर्ता के पर्यवेक्षक ने शैक्षिक नैतिकता के इस मानक का अनुरक्षण नहीं किया है तो स्कूल शो० स० कुलपति को, संबंधित पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक द्वारा कम से कम तीन वर्ष तक शोध छात्रों का पंजीकरण करने से विवर्जित करने के लिये संस्तुत कर सकेगी। कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

9.10.3 स्कूल शो० स० द्वारा अनुमोदित शोध पत्र के प्रस्तुति पूर्व सारतत्व और अंतिम-शीर्षक की प्राप्ति पर स्कू० शोध स० अध्या०, संबंधित स्कू० शो० स० द्वारा अनुमोदित परीक्षक सूचिका तथा प्रस्तुति पूर्व सार तत्व परी० निय० को उपरोक्त दस्तावेज प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर-भीतर भेज देंगे। इन शोध प्रबंधों के मूल्यांकन के लिये उक्त सूचिका से बाह्य शोध प्रबंध मूल्यांकन(ि) की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जायेगी। परीक्षक-सूचिका में कुलपति और नाम भी जोड़ सकते हैं।

9.10.4 विद्यावाचस्पति शोध के मूल्यांकन हेतु कार्य रीतियों का अनुसरण परीक्षा प्रभाग कुलपति द्वारा अनुमोदन की अनुरूपता में करेगा।

### 9.11 विद्यावाचस्पति शोध प्रबंध का मूल्यांकन

9.11.1 प्रत्येक परीक्षक से अनुरोध किया जायेगा कि वे शोध प्रबंध प्राप्त होने की तिथि से 06 सप्ताह के अन्दर, निर्धारित प्रपत्र (परीक्षा प्रभाग द्वारा अभिकल्पित तथा परीक्षा नियंत्रक द्वारा स्वीकृत) पर विस्तृत मूल्यांकन प्रतिवेदन और अपनी अनुशंसाएँ परी० निय० को प्रेषित करें।

9•11•2 ऐसी परिस्थिति में, जबकि शोध प्रबन्ध का प्रेषण तिथि से 3 मास के अन्दर परीक्षक से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो विद्या वाचस्पति शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन के लिये, परीक्षकों की अनुमोदित सूचिका से कुलपति किसी अन्य परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं।

9•11•3 परीक्षक से अपेक्षा होगी कि वे सुनिश्चित/सुस्पष्ट ढंग से यह सूचित करें कि क्या उनके मतानुसार विद्या वाचस्पति शोध प्रबन्ध:

- (क) विद्या वाचस्पति उपाधि को (मौखिक प्रतिवाद के बाद) प्रदान किये जाने के लिये स्वीकार कर लिया जाना चाहिये, अथवा
- (ख) विद्या वाचस्पति उपाधि (सुझाये गये बदलावों को सम्मिलित किये जाने की शर्त और मौखिक प्रतिवाद के बाद) प्रदान किये जाने के लिये स्वीकार कर लिया जाना चाहिये, अथवा
- (ग) संशोधित प्रपत्र पर पुनर्प्रस्तुति, अथवा
- (घ) अस्वीकृत

9•11•4 विद्या वाचस्पति शोध प्रबन्ध की पुनर्प्रस्तुति/अस्वीकरण की संस्तुति हेतु परीक्षक कारण दर्शायेंगे। यदि पुनर्प्रस्तुति की संस्तुति दर्शायी गयी है तो परीक्षक विशिष्ट रूप से उन आशोधनों को सुझायेंगे जिनका विद्या वाचस्पति शोध प्रबन्ध में निर्वहन किया जाना, शोध छात्र के लिये आवश्यक है। स्कूल-अधिष्ठाता के परामर्श से परीक्षा नियंत्रक शोधार्थी और पर्यवेक्षक को उन सभी संशोधनों और आशोधनों की सूची उपलब्ध करायेंगे जो परीक्षक के परामर्शानुसार शोध प्रबन्ध में किये जाने अपेक्षित हैं।

9•11•5 यदि भारी बदलाव किये जाने हैं और पुनर्प्रस्तुति/पुनर्मूल्यांकन की संस्तुति की गयी है तो परीक्षा नियंत्रक से इस संबंध में सूचना प्राप्त हो जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर पर्यवेक्षक के परामर्श से शोध छात्र संशोधित वृत्तांत पुनर्प्रस्तुत कर सकता है। तथापि, अपवादिक परिस्थितियों में स्कूल शो0 स0 इस अवधि को एक और वर्ष के लिये बढ़ा सकती है लेकिन यह सकल परिशोधन अवधि, दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। ये संशोधित विद्या वाचस्पति शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु पुनः उन्हीं परीक्षक(ों) के पास भेज दिये जायेंगे जिन्होंने संशोधनों की सिफारिश की थी। यदि उनमें से कोई भी, संशोधित शोध की परीक्षा करने से मना कर देता है तो अनुमोदित नामावली से एक अतिरिक्त परीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है और उन्हें, संशोधित शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन को सुगम बनाने के लिये विगत परीक्षक(ों) की टिप्पणियाँ सुलभ करायी जायेंगी।

## 9•12 मौखिक प्रतिवाद/मौखिक परीक्षा

9•12•1 विद्या वाचस्पति शोध प्रबन्ध के समर्थन में विद्या वाचस्पति शोध छात्र के मौखिक प्रतिवाद/मौखिक परीक्षा तथी आयोजित किये जायेंगे। यदि शोध प्रबन्ध पर दोनों बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक होगी और शोध प्रबन्ध की स्वीकार्यता के लिये तथा मौखिक परीक्षा आयोजित किये जाने के लिये विशिष्ट अनुशंसा उसमें सम्मिलित की गयी होगी। यदि, विद्या वाचस्पति शोध प्रबन्ध को दोनों बाह्य परीक्षकों द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो बिना किसी आगामी क्रिया के शोध प्रबन्ध को अस्वीकृत मान लिया जायेगा तथा शोध छात्र को उपाधि (डिग्री) प्रदान किये जाने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। विद्या वाचस्पति शोध प्रबन्ध के मामले में, बाह्य परीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्टों में से यदि एक रिपोर्ट असंतोषजनक है और मौखिक परीक्षा की संस्तुति नहीं मिलती तो विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा शोध प्रबन्ध को परीक्षकों की स्वीकृत नाम सूचिका के बाहर से किसी विकल्पी बाह्य परीक्षक को भेज देगी और मौखिक परीक्षा भी केवल तब ही आयोजित की जायेगी यदि वैकल्पिक परीक्षक द्वारा दी गयी रिपोर्ट संतोषजनक होगी तथा इन वैकल्पिक परीक्षक ने शोध कार्य की स्वीकार्यता को संस्तुति दे दी होगी। यदि वैकल्पिक परीक्षक भी असंतुष्ट है और धोध काग्र की स्वीकृति

की संस्तुति नहीं देता तो शोध प्रबन्ध, डिग्री प्राप्ति के लिये अपात्रता-पूर्ण घोषित कर दिया जायेगा। विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा विद्या वाच० शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन की सकल प्रक्रिया तथा मौखिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा शोध प्रबन्ध के जमा कराने की तिथि से 6(छः) माह के भीतर ही निपटा देगा।

9•12•2 संतोषजनक विद्या वाच० शोध मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद एक शोध छात्र को, विधिवत रूप से गठित एक समिति, जिसे बाद में मौखिक प्रतिवाद समिति (ओडीसी) के नाम से उल्लिखित किया जायेगा, के समक्ष मौखिक रूप से अपने कार्य/शोध कार्य का समर्थन करना अपेक्षित होगा।

9•12•3 इस मौखिक प्रतिवाद समिति में, संबंधित छात्र की शोध परा स० के अध्यक्ष पर्यवेक्षक(ई) (कम से कम एक उपस्थित होने चाहियें) तथा एक वे बाह्य परीक्षक जिन्होंने शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन किया हो और जो कुलपति द्वारा नियुक्त किये गये हों, सम्मिलित होंगे। यदि मौखिक प्रतिवाद आयोजित करने के लिये शोध प्रबन्ध के मूल्यांकक परीक्षक उपलब्ध न हों तो अनुमोदित परीक्षकों की नामिका में से किसी एक वैकल्पिक परीक्षक की नियुक्ति कुलपति द्वारा कर दी जायेगी।

9•12•4 यदि आवश्यक समझा जाये, तो शोध छात्र के द्वारा उन्मुक्त मौखिक परीक्षा एवं प्रतिवाद, कुलपति की पूर्व स्वीकृति से स्काइप/दृश्य दूर संलाप के माध्यम से आयोजित किये जा सकते हैं।

9•12•5 मौखिक परीक्षा के चरम के साथ परीक्षा के सभी स्तरों की निष्पत्ति के बाद मौखिक प्रतिवाद समिति (मौ०प्रति०समिति) निर्धारित प्रपत्र (परीक्षा प्रभाग द्वारा अभिकल्पित और परीक्षा नियंत्रक द्वारा स्वीकृत) पर अपनी रिपोर्ट परी०निय० के माध्यम से कुलपति को निम्न में से एक संस्तुति के साथ भेजेगी:

- (i) कि उपाधि (डिग्री) प्रदान कर दी जाये।
- (ii) कि शोधकर्त्त को किसी बाद की तिथि पर नये सिरे से मौखिक प्रतिवाद के लिये प्रस्तावित किया जाये।
- (iii) कि उपाधि प्रदान न की जाये।

9•12•6 मौ० प्रति० समि० की अनुशंसाओं पर कुलपति का निर्णय परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति के निर्णय की तिथि उद्धृत करते हुए अधिसूचित किया जायेगा जो कि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्या वाचस्पति की उपाधि के औपचारिक रूप से प्रदान किये जाने की प्रभावी तिथि के रूप में निर्धारित होगी। इस अधिसूचना से पूर्व, परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित कर लेंगे कि शोध छात्र ने विद्या वाचस्पति शोध प्रबंध की एक सॉफ्ट प्रति तथा दो हार्ड बाउंड प्रतियाँ, एक संबंधित स्कूल के पुस्तकालय के लिये और दूसरी विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय के लिये प्रदोन कर दी हैं। इनमें पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित सभी आवश्यक शुद्धियाँ/आशोधन सम्मिलित किये होने चाहिये और शोध प्रबंध के प्रारम्भ में एक पृथक पन्ने पर निम्न स्वत्वाधिकार प्रमाण पत्र दिया जातना चाहिये:

© गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, द्वारका, नयी दिल्ली-110078 सर्वाधिकार सुरक्षित।

9•12•7 विद्या वाचस्पति (पीएचडी) अधिसूचना के बाद और दीक्षांत समारोह के समय अंतिम उपाधि प्रदान किये जाने के समय विश्वविद्यालय शोध छात्र को विद्या वाचस्पति पूर्ण हो जाने का अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगा इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ कि विद्या वाचस्पति की डिग्री वि०वि० अनु० आयोग के विनियमों की अनुरूपता में प्रदान की गयी है। प्रमाणपत्र और डिग्री में स्कूल, अध्ययन-संस्थान तथा वह विषय (विद्या शाखा) जिसके लिये विद्यावाचस्पति (पी०एच०डी) डिग्री प्रदान की गयी है का उल्लेख किया जायेगा।

10•0 विद्या वाचस्पति कार्यक्रम प्रस्तावित करने के लिये मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा पूर्ण की जाने वाली शैक्षणिक, शोध, प्रशासनिक और अधिसंरचनात्मक अपेक्षाएँ।

- 10•1 सम्बद्ध महाविद्यालयों को वि० वाच० कार्य० प्रस्तावित करने योग्य पात्र केवल तभी समझा जायेगा यदि वे पात्र शोध-पर्यवेक्षक, अपेक्षित आधारित संरचना तथा सहाय्य प्रशासनिक एवं शोध उन्नयन सुविधा धारी होंगे।
- 10•2 संबद्ध महाविद्यालयों को अबाध और सतत् प्रकार्यात्मक स्थिति में कम से कम 5 वर्ष अथवा अधिक समय से अस्तित्व में होना चाहिये। 4 वर्ष के स्नातक पूर्व कार्यक्रमों तथा/अथवा परास्नातक कार्यक्रमों को संबंधित विद्याध्ययन में कम से कम दो विद्या वाचस्पति अर्हता-प्राप्त शिक्षकों/अन्य शैक्षणिक कर्मियों (वैज्ञानिकों) के सान्निध्य में प्रस्तावित किये जाने वाला होना चाहिये। उपखण्ड 10•3 के अंतर्गत अनुबंधित इस अध्यादेश के अनुसार सहाय्य प्रशासनिक एवं शोध-उन्नयन सुविधाओं सहित, अपेक्षित आधारीक संरचनाएँ होनी चाहिये; उन्हें केवल तथी परा-स्नातक/4 वर्षीय स्नातक पूर्व कार्यक्रमों वाले अध्ययन विषयों में विद्या वाचस्पति कार्यक्रम प्रस्तावित करने हेतु पात्र समझा जायेगा। विद्या वाचस्पति कार्यक्रम प्रस्तावित करने हेतु संबद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से आवश्यक मान्यता प्राप्त कर लेनी चाहिये।
- 10•3 निम्न उद्धृतानुसार, शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं वाले संबद्ध महाविद्यालयों के विभागों द्वारा विद्यावाचस्पति कार्यक्रम प्रस्तावित किये जाने की अनुमति होगी।
- 10•3•1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों के मामलों में कम्प्यूटर सुविधाओं एवं आवश्यकता सॉफ्टवेयर तथा अबाध बिजली और पानी की आपूर्ति के साथ प्रत्येक शोध छात्र के लिये पर्याप्त स्थान के प्रावधान सहित संबंधित संस्थान द्वारा विनिर्दिष्टानुसार परिष्कृत उपकरणों के साथ विशिष्ट प्रयोगशालाएँ होनी चाहिये।
- 10•3•2 विभाग/प्रस्तकालय में पढ़ने-लिखने, अध्ययन और शोध सामग्री शोध छात्रों द्वारा संचित करने के लिये सभी विषयों हेतु बढ़ाये गये कार्य समय और पर्याप्त स्थल सहित आधुनिक पुस्तकें, जर्नल्स, ई-जर्नल्स से सज्जित उद्दिष्ट पुस्तकालय संसाधन शोध छात्रों के लिये उपलब्ध होने चाहिये।
- 10•3•3 विशिष्ट विषयों में विद्या वाचस्पति कार्यक्रम प्रस्तावित करने के लिये, मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से संबद्ध महाविद्यालय निदेशक, अनु० तथा वि० प्रकोष्ठ को आवेदन करेगा। विद्या वाचस्पति कार्यक्रम प्रस्तावित करने के लिये विचारार्थ किसी महाविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप निदेशक अनु० तथा वि० प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया गया होगा। कुलपति की स्वीकृति के बाद निदेशक; अनु० तथा वि० प्र० विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर इस आवेदन पत्र को अधिसूचित करेंगे।
- 10•3•4 ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालयों को विद्या वाचस्पति कार्यक्रम प्रस्तावित करने की अनुमति, केवल सम्बद्ध महाविद्यालय का विद्या वाच० कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये अपेक्षित आधारीक संरचना एवं अन्य सुविधाओं के मूल्यांकन करने के लिये दौरा करने हेतु कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति से प्राप्त संतोषजनक रिपोर्ट मिलने के बाद ही दी जा सकेगी।
- 10•3•5 संबंधित वि० वि० अध्य० स्कू० की स्कूल शोध स० ही उन विशिष्ट विषयों(ि) का निर्णय लेगी जिसमें विद्या वाचस्पति कार्यक्रम प्रस्तावित किये जाने हैं तथा 10•3•1 एवं 10•3•2 खण्डों के अनुसार उन विस्तृत अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करेगी जो कि विद्या वाचस्पति कार्यक्रम प्रस्तावित करने तथा इस अध्यादेश में विनिर्दिष्टानुसार अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु विचारार्थ किसी महाविद्यालय के आवेदन पर विचार करने के लिये आवश्यक है।
- 10•3•6 कुलपति के अनुमोदन के उपरान्त निदेशक, अनु० तथा वि० प्रको० संबद्ध महाविद्यालय के लिये अन्य अपेक्षित पात्रता मापदण्ड भी अधिसूचित कर सकते हैं।

- 10•4 सम्बद्ध महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय की संतुष्टि के स्तर के नियमित और अर्हता प्राप्त कर्मी होने चाहियें। इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार जो भी पात्रता अर्हताओं और अनुभवों पर खरा उतरते होंगे तो ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षण स्टाफ में से ही, इस अध्यादेश के खण्ड 5 में निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्बन्धित उन्हीं के वि०वि०अध्य०स्कूल की स्कूल शोध समि० द्वारा उन्हीं को "पर्यवेक्षक" के रूप में अनुमोदित किया जायेगा।
- 10•5 सम्बद्ध महाविद्यालय में किसी विषय विशेष में शोध छात्रों के प्रवेश हेतु प्रक्रिया वि०वि०अध्य०स्कूल/केन्द्र स्तर पर गठित प्रवेश समिति के माध्यम से पूरी होगी। किसी विषय विशेष में 4 वर्षीय उपाधि कार्यक्रम अथवा विषय विशेष में परास्नातक कार्यक्रम के लिये, यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में विद्या वाचस्पति कार्यक्रम प्रस्तावित किया जाता है तो सम्बन्धित वि०वि०अध्य०स्कूल की स्कूल शोध स०, विशिष्ट सम्बद्ध महाविद्यालय हेतु, विषय के स्कूल शोध सं० की भूमिका का निर्वाह करेंगे। यदि सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रविष्ट विशिष्ट शोध छात्र से संबंधित किसी भी कार्यक्रम (एजेन्डे)/मद पर स्कूल शोध मि० द्वारा विचार विमर्श किया जाता है तो स्कूल शोध स० की बैठक में शोध छात्र के पर्यवेक्षक को भी आमंत्रित किया जायेगा।
- 10•6 सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रविष्ट प्रत्येक शोध छात्र के लिये सम्बद्ध महाविद्यालय में एक शोध परामर्श समिति (आरएसी) का गठन ठीक उसी संघटन और प्रकार्य के साथ किया जायेगा जैसा कि इस अध्यादेश के खण्ड 8 में परिभाषित है। शो०परा०स० के सदस्य, सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित पर्यवेक्षक होंगे। तथापि, शोध परा० स० के अध्यक्ष सम्बन्धित वि०वि०अध्य० स्कूल की स्कूल शो०स० के सदस्य होंगे।
- 10•7 शोध छात्र, इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप ही पाठ्यक्रम कार्य एवं अन्य दूसरी औपचारिकताएँ निपटाएंगे।
- 10•8 शोधकार्य पूर्ण हो जाने पर, शोध छात्र अपने विद्या० वाच० कार्यक्रम की प्रस्तुति— पूर्व सार की 08 प्रतियाँ पर्यवेक्षक एवं शोध सलाहकार समिति के माध्यम से संबंधित वि०वि०अध्य०स्कूल की स्कूल शो०स० को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे शोधार्थी की प्रस्तुति—पूर्व, संबंधित वि०वि०अध्य०स्कूल की स्कूल शोध समिति, शोध परा० स० के अध्यक्ष, शो० परा० सं० सदस्य और संबंधित शोध छात्र के पर्यवेक्षक के समक्ष की जानी चाहिये।
- 10•9 विश्वविद्यालय ऐसे विद्या वाचस्पति कार्यक्रमों के लिये अनुरोध को नहीं स्वीकार करेगा जिनके लिये विश्वविद्यालय में स्कूल शोध समि० नहीं है।
- 10•10 सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिये कोई भी आवेदन/निरंतरता शुल्क नहीं होगा। इस प्रकार से मान्यता प्राप्त कोई भी महाविद्यालय शोध छात्र से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क, उन शुल्कों जो गु०गो०सिंह इ०प्र० वि०वि० समय—समय पर निर्धारित करता है जैसे पंजीकरण, वार्षिक शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क तथा शोध ग्रन्थ जमा करने का शुल्क को छोड़कर वसूल नहीं कर सकता है।
- 10•11 गु० गो० सिंह इ०प्र०वि० वि०अध्येतावृत्ति नीति के अनुसरण में सम्बद्ध महाविद्यालय भी अपने—अपने महाविद्यालय में समावेशी शोध वातावरण निर्मित करने के ध्येय से शोध छात्रों के लिये शोध अध्येतावृत्ति प्रस्तावित कर सकते हैं।
- 10•12 इन सम्बद्ध महाविद्यालयों में से किसी में भी प्रवेश प्राप्त प्रत्येक शोध छात्र को, विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय निर्धारित शुल्क आदि का पृथक्तः भुगतान करना होगा।
- 10•13 इस प्रकार के समस्त संबद्ध महाविद्यालय, अनुप्रयोज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालयी अध्यादेश शासी कार्यक्रम जो कि विद्या वाचस्पति उपाधि अर्जन में सहयोगी होते हैं, विश्वविद्यालय

नियम-विनियम, संबंधित स्कूल शोध समिति तथा निदेशक, अनु० तथा विका० प्रको० द्वारा जारी मार्गदर्शन एवं निदेशों अनुरूपता में प्रकाय करेंगे।

### 11•0 अंशकालिक विधि द्वारा विद्या वाचस्पति

11•1 विद्यावाचस्पति कार्यक्रम दूरस्थ और/अथवा ऑनलाइन शिक्षण विधि द्वारा प्रस्तावित नहीं होगा।

11•2 अंशकालिक विद्या वाचस्पति केवल नियोजित अभ्यर्थियों के लिये ही अनुमत होगी लेकिन इस अध्यादेश में उद्धृत शर्तें भी पूरी की गयी होनी चाहियें। पूर्णकालिक पंजीकरण से अंशकालिक पंजीकरण और अंशकालिक पंजीकरण से पूर्णकालिक पंजीकरण में परिवर्तन की अनुमति, विद्या वाचस्पति कालावधि में मामला दर मामला आधार पर शो० परा० सं० की अनुशंसा पर संबंधित स्कूल की स्कू०शो० सं० द्वारा लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए दी जायेगी। स्कूल शो० सं० का निर्णय अभिलिखित किये जाने के उद्देश्य से अनु० तथा वि० प्रको० को संप्रेषित कर दिया जाना चाहिये।

11•3 अभ्यर्थी जहाँ नियोजित है विश्वविद्यालय उसके उपयुक्त प्राधिकारी से अंशकालिक विद्या वाचस्पति कार्यक्रम के लिये अभ्यर्थी के माध्यम से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगा कि:

- (i) अभ्यर्थी को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुपत्ति दी जाती है।
- (ii) शोध कार्य में पर्याप्त समय लगाने के लिये उनकी कार्यालयी ड्यूटी अनुमति देती है।
- (iii) यदि आवश्यकता पड़ी तो अपना अध्ययन कार्य पूरा करने के लिये उन्हें ड्यूटी से मुक्त कर दिया जायेगा।

11•4 अंशकालिक शोधार्थियों को पाठ्यक्रम कार्य प्रस्तावित किया जायेगा। अंश कालिक शोधकर्त्ताओं को इस अध्यादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा।

### 12•0 इन्फ्लिबनेट (INFLIBNET) के साथ निक्षेपागार

मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात् और विद्या वाचस्पति उपाधि(यों) के प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व परीक्षा प्रभाग, विद्यावाचस्पति शोध प्रबन्ध की एक इलैक्ट्रॉनिक प्रति, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को उपलब्ध करायेगा। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष, निर्धारित संरूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिये अमिहित किसी अन्य आँकड़ा संचय अथवा शोध गंगा या इन्फ्लिबनेट के साथ निक्षेप हेतु सहमति पत्र के अनुसार उक्त प्रति इन्फ्लिबनेट को प्रस्तुत किये जाने को सुनिश्चित करेंगे।

### 13•0 अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करना

वास्तविक उपाधि दिये जाने से पूर्व विश्वविद्यालय का परीक्षा प्रभाग इस आशय का एक अनंतिम प्रमाण जारी करेगा कि अनुप्रयोज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उपाधि (डिग्री) प्रदान कर दी गयी है।

14•0 पहले से ही पंजीकृत ऐसे शोधार्थियों, जिन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत नहीं किया है, के विषय में विचार-विमर्श पहले से ही पंजीकृत शोध छात्रों के प्रवेश के समय लागू अध्यादेश की प्रभावी होगा।

15•0 इस अध्यादेश के अधिनियम से पहले विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पर्यवेक्षकों की पात्रता की सम्बन्धित स्कूल शो० सं० द्वारा समीक्षा की जायेगी।

16•0 सम्बद्ध महाविद्यालयों से सम्बन्धित पर्यवेक्षकों के संदर्भ में, सबसे पहले तो इस अध्यादेश के खण्डों के अनुसार विद्यावाचस्पति कार्यक्रम प्रस्तावित करने वाले सम्बद्ध महाविद्यालय के रूप में अनुमोदित होना

चाहिये। इसके लंबित होने की स्थिति में, सम्बद्ध महाविद्यालयों के पर्यवेक्षकों को अपने पर्यवेक्षण के अधीन नये शोधकर्ता पंजीकृत करने की अनुमति नहीं होगी; इसका, इस अध्यादेश के अधिनियम से पूर्व पंजीकृत हुए शोधकर्ताओं का उनके द्वारा पर्यवेक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर्यवेक्षकों की मान्यता हेतु प्रचालनात्मक मार्गदर्शिका कुलपति के अनुमोदन के उपरान्त अनु० तथा वि० प्र० के द्वारा जारी की जायेगी।

- 17•० प्रवेश शुल्क, वार्षिक सत्ता शुल्क एवं शोध-प्रबन्ध जमा करने का शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।
- 18•० विश्वविद्यालय के नियमित पूर्णकालिक नियोजन में केवल मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षकों के अन्तर्गत वि०वि०अध्य० स्कूल में प्रविष्ट हो चुके पात्र पूर्णकालिक शोध छात्रों को वित्तिय सहयोग के लिये प्रावधान (यदि कोई हो तो), विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।
- 19•० प्रवेश विवरणिका की तैयारी और जारी करने के लिये प्रचालन मार्गदर्शिका निदेशक अनु सं० तथा विकास प्रको० द्वारा प्रस्तावित की जायेगी और कुलपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात् लागू कर दी जायेगी।
- 20•० विद्या वाचस्पति शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन हेतु प्रचालन मार्गदर्शिका परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तावित की जायेगी और कुलपति महोदय के अनुमोदन-पश्चात् जारी कर दी जायेंगी।
- 21•० इस अध्यादेश में किसी बात का उल्लेख न होने पर भी, यदि विद्यावाचस्पति कार्यक्रम का नियमन करने वाले संविधिक निकाय किसी ऐसी स्थिति/विनिर्दिष्टता को परिभाषित करती है जो कि प्रवेश पात्रता अथवा प्रक्रिया से सम्बन्धित हो, जो कि इस अध्यादेश की विसंगति में हो तो वह तब तक कुलपति महोदय की स्वीकृति से अनुप्रयोज्य रहेंगी, जब तक कि उक्त नयी शर्तों/विनिर्देशों को सम्मिलित करते हुए इस अध्यादेश में आवश्यक संशोधन नहीं कर किये जाते। संबंधित स्कूल शोध समिति इसकी समाविष्टि को प्रस्तावित करेगी।
- 22•० इस अध्यादेश में किसी भी ऐसी बात के न होते हुए भी किन्हीं अप्रत्याशित मुद्दों के उठ जाने और जो इस अध्यादेश की व्याप्ति में न हों अथवा व्याख्या में मतभेद होने की स्थिति में निदेशक, अनु० तथा विका० प्रको० स्कूलों के किसी अथवा सभी अधिष्ठाताओं से गठित समिति से मत/सलह लेने के बाद कुलपति निर्णय ले सकेंगे। कुलपति महोदय कर निर्णय अंतिम होगा।

यह संशोधित अध्यादेश, प्रबंध मंडल द्वारा दिये गये अनुमोदन की तिथि अर्थात् 28.04.2023 से लागू होगा।

आदेशानुसार,

डॉ. कमल पाठक कुलसचिव

## GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY NOTIFICATION

Delhi, the 9th January, 2025

**F.No.GGSIPU/Coord/79<sup>th</sup>BOM/Ord.12(Revised)/2023-24/434—In pursuance** of the provisions of Section 27 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act, 1998 (9 of 1998), the Board of Management of Guru Gobind Singh Indraprastha University in its 79<sup>th</sup> meeting held on 28<sup>th</sup> April 2023 vide agenda item 79.13 has revised Ordinance 12 'Governing programmes leading to the Degree of Doctor of Philosophy' notified vide No. IPV/JR(C)/BOM48/2011/531 dated 24.09.2012 as detailed below:

**Ordinance 12: Governing Programmes leading to the Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.)**

**Applicability:** This Ordinance shall apply to all programmes leading to the degree of Doctor of Philosophy (applicable from the academic session 2023-24). The Ordinance shall come into force from the date of approval of the Board of Management.

**1.0 Definitions**

- 1.1. **“Act”** shall mean the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act, 1998, as amended from time to time.
- 1.2. **“University”** shall mean Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi.
- 1.3. **“School of Studies”**, also referred to as School(s) or University School of Studies (USS) shall mean Schools of Studies established by the University as per clause 1.0 of Ordinance 2.
- 1.4. **“Centre”** shall mean Centre of Excellence established by the University as per clause 1 of Ordinance 35.
- 1.5. **“College/Institute”** shall mean an academic institution maintained or admitted by the University to its privileges and includes an affiliated college/institute as defined in section 2(i) of the Act and approved for Ph.D. programme as per the provisions of this Ordinance.
- 1.6. **“Board of Studies (BOS)”** shall have the same meaning as the Board of School of Studies defined under clause 2 of Ordinance 2 of the (USS) concerned. The term 'Board of Studies' herewith shall also apply to the 'Steering Committee' of the Centre(s). The role of the Steering Committee shall be equivalent to the role of BOS as defined above in addition to its role defined in the Ordinance 35. Furthermore, the constitution of the Steering Committee shall be as defined in Ordinance 35. Wherever the term BOS is used in this Ordinance, hereafter, it should be read as 'Steering Committee' in the context of the Centre constituted under Ordinance 35.
- 1.7. **“RDC”** shall mean the Research and Development Cell of the University.
- 1.8. **“Course Work”** means courses of study prescribed by the School/Department/ Centre to be undertaken by a student registered for the Ph.D. Degree
- 1.9. **“COE”** shall mean the Controller of Examinations of the University.
- 1.10. **“Discipline”** shall mean the discipline(s) in which the Ph.D. degree is awarded as mentioned in the Ph.D. degree certificate. The SRC shall recommend and BOS of the concerned School shall approve the discipline(s) in which Ph.D. Degree shall be offered through the School. The Dean of the concerned School shall communicate the discipline(s) in which Ph.D. Programme is offered in the School, after approval of the BOS, to the RDC for notification.
- 1.11. **“Academic Session”** shall be of one-year duration apportioned into two semesters of six months. The Academic Session shall ordinarily commence from the first working day of the month of August every year. The RDC shall notify the detailed academic calendar for the conduction of the coursework part of the Ph.D. programme while the academic calendar for the review of Ph.D. dissertation/thesis work shall be notified by the concerned SRC.
- 1.12. **“Research Scholar”** shall mean a person registered for Ph.D. under the provisions of this ordinance, also called “scholar”.
- 1.13. **“Foreign Research Scholar”** shall mean foreign nationals or persons of Indian origin registered for Ph.D. as a research scholar, under the provisions of this ordinance.
- 1.14. **“Foreign Educational Institution”** means—(i) an institution duly established or incorporated in its home country and offering educational programmes at the undergraduate, postgraduate and higher levels in its home country and (ii) which offers programme(s) of study leading to the award of a degree through conventional face-to-face mode, but excluding distance, online, ODL mode.

- 1.15. “**Plagiarism**” means the practice of taking someone else’s work or idea and passing them as one’s own.
- 1.16. “**Adjunct Faculty**” means a part-time or contingent instructor, but not a full-time faculty member hired to teach by Guru Gobind Singh Indraprastha University.
- 1.17. “**Supervisor**” shall mean a qualified and recognized faculty member of the University or affiliated college as stipulated in this Ordinance.
- 1.18. “**Co-Supervisor**” shall mean an additional “**supervisor**” assigned to a “**research scholar**” under the provisions of this Ordinance.
- 1.19. “**Caretaker Supervisor**” shall mean an alternative “**supervisor**” assigned to a “**research scholar**” to act as his/her supervisor in the absence of the original supervisor under the provisions of this Ordinance.
- 1.20. “**SRC**” shall mean the School Research Committee, consisting of the Dean of the concerned School as the Chairperson, and all recognized supervisors of the University in the discipline(s) in which the Ph.D. programme is offered through the School. The Schools that offer Ph.D. degree in multiple disciplines may have a separate SRC for each such discipline as needed, provided that each such SRC has no less than three members from the concerned discipline. In addition, there should be at least two common members in all such discipline-specific SRCs of the concerned School. The term ‘SRC’ herein shall also apply to the ‘Centre Research and Consultancy Committee’ (CRCC) of a Centre. The role of CRCC shall be equivalent to the role of SRC as defined above, in addition to its role defined in the Ordinance 35. Furthermore, the constitution of CRCC shall be as defined in Ordinance 35. Wherever the term SRC is used in the Ordinance, hereafter, it should be read as CRCC in the context of the Centre constituted under Ordinance 35.
- 1.21. “**Admission Committee**” shall mean a committee consisting of all prospective (recognized) supervisors with vacant slots in a School/discipline and intending to take research scholars in that admission session, subject to a minimum of 5 members, including the Dean and one member from the SC/ST category. The SRC shall constitute the admission committee. The condition of being a recognized supervisor or having vacant slots for that year or belonging to the same school/discipline shall be relaxed, if needed, to ensure representation from the SC/ST category, through a recorded decision of the SRC. If the total number of available members to constitute this committee is less than 5, then other recognized supervisors may be co-opted from within the School or from any other University School/ centre within the University campus offering programmes in an allied discipline, through a recorded decision of the SRC. This committee shall be chaired by the Dean of the concerned School and shall be responsible for the interview and allotment of selected research scholars for Ph.D. in a particular academic session.
- 1.22. “**External examiner**” means an academician/researcher with published research work who is not part of the University where the Ph.D. scholar has registered for the Ph.D. programme, and as further detailed in this Ordinance.
- 1.23. “**Commission**” shall mean University Grants Commission in this Ordinance.
- 1.24. “**PET**” shall mean Ph.D. entrance test to be conducted by the Examination branch of the University.

1.25. “**RAC**” shall mean Research Advisory Committee.

**Note:** In this Ordinance wherever ‘He’ and ‘His’ occurs, these shall mean to imply ‘he/she’ and ‘his/her’, respectively.

## **2.0 Minimum Eligibility criteria for admission to Ph.D. Programme(s)**

2.1 The following are eligible to seek admission to the Ph.D. Programme:

2.1.1 Candidates who have completed a 1-year/2-semester master's degree programme after a 4-year/8-semester bachelor's degree programme, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed; OR

2.1.2 Candidates who have completed a 2-year/4-semester master's degree programme after a 3-year bachelor's degree programme or qualifications declared equivalent to the master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed; OR

2.1.3 Candidates seeking admission after a 4-year/8-semester bachelor's degree programme should have a minimum of 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed; OR

2.1.4 Candidates who have completed the M.Phil. programme with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed; OR

2.1.5 Candidates who have an equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of the educational institution.

2.1.6 In cases where the marks of the qualifying examination are not given by the degree awarding recognized University/ Institution, such as in case of M.D.S., M.D., M.S., D.M., M.Ch., etc, candidates, who have obtained a minimum of 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed, in the relevant undergraduate examination, shall be considered eligible to seek admission to the Ph.D. programme.

In such cases, the concerned candidates shall be required to submit an undertaking that their University/Institution does not give marks for the said qualifying examination.

2.2 A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-Baled/Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

2.3 Every School's SRC shall define the detailed eligibility criteria, which minimally should be in broad consonance with the specification of this Ordinance, and the same after

approval of the Board of Studies shall be communicated to the RDC for incorporation in the admission brochure.

### **3.0 Procedure for Admission**

- 3.1 Admission to the Ph.D. programme of studies shall be through an entrance test (PET) to be conducted by the University in the relevant discipline(s) of study once in an academic year.
- 3.2 For those students who qualify for fellowship/scholarship in UGC-NET (JRF)/UGC-CSIR NET (JRF)/GATE/CEED and similar National level tests shall be exempted from the entrance test conducted by the University for admission to the Ph.D. programme. However, they shall have to apply for admission to the University, as and when, the University invites application for admission to the Ph.D. programme.
- 3.3 Every School's SRC shall specify the disciplines in which the Ph.D. programmes are offered in the concerned School, and after the approval of the BOS, the same shall be communicated to the RDC for incorporation in the admission brochure. A discipline of study for the Ph.D. programme shall be offered by only one School. If multiple Schools desire to offer the same discipline of study, then the matter should be put up before the Academic Council for its consideration & resolution. The decision of the Academic Council shall be final.
- 3.4 The admission brochure for Ph.D. programmes shall specify the number of available seats for admission, subject / discipline-wise distribution of available seats, criteria for admission, procedure for admission and modalities of conduct of PET and all other relevant information for the benefit of the candidates.
- 3.5 The number of seats (tentative) available in a particular discipline for Ph.D. shall be a part of the admission brochure issued for admissions to the Ph.D. programmes. The SRC of the concerned discipline shall decide on an annual basis a predetermined and manageable number of Ph.D. scholars to be admitted in an academic session, depending on the number of available Research Supervisors and other academic and physical facilities available. The total number of slots/seats for admission of research scholars to the Ph.D. programme may be increased by the SRC of the concerned USS/Centre. However, the increase shall be limited to seats/slots only under those supervisors who have given non-zero slots/seats for admission in a particular discipline. The final list of available vacant slots/seats shall be displayed by the concerned USS/Centre on the University website together with the schedule of the interview to be conducted for admission to the Ph.D. programme.
- 3.6 Reservation shall be as per the State Reservation Policy, notified by the University from time to time.
- 3.7 The advertisement and the brochure for the Ph.D. programmes shall be proposed by the Director, RDC and after approval of the Competent Authority of the University, shall be put in the public domain.
- 3.8 The advertisement for admission to Ph.D. programmes shall be in at least two national newspapers out of which at least one shall be in Hindi language.
- 3.9 The Entrance Test syllabus shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject-specific. The written entrance test shall be qualifying for admission to the

Ph.D. programme with 50% as the qualifying cut-off. A relaxation of 5% marks will be allowed in the entrance examination for the candidates belonging to SC/ST/OBC/ differently-abled category/ Economically Weaker Section (EWS), and other categories of candidates as per the decision of the Commission from time to time.

- 3.10 The detailed syllabus for the written entrance test shall be approved by the SRC of the concerned discipline, and forwarded to the RDC for incorporation in the admission brochure.
- 3.11 The concerned SRC of the specific discipline of each USS may decide the number of eligible students to be called for an interview based on the number of Ph.D. seats available in each academic session. Subject to the availability of eligible students in a particular discipline of the Ph.D. programme and category of reservation, the minimum seat/slot: student ratio shall be 1:3. If the number of eligible students are less than the ratio specified (1:3), then all eligible candidates shall be called for interview.
- 3.12 An interview shall be organized where the candidates are required to discuss their research interest/area through a presentation before a duly constituted Admission Committee.
- 3.13 The admission shall be based on the performance /merit of the candidate in the interview conducted by the Admission Committee of the concerned School. The interview shall consider the following aspects, viz. whether:
- (a) The candidate possesses the basic knowledge and aptitude for the proposed research work;
  - (b) the candidate possesses the competence for the proposed research work;
  - (c) the proposed plan of research can contribute to new/additional knowledge in the area of research.

For written entrance test qualified candidates, the merit list (out of 100 marks) will be prepared for the candidates whose research proposals are accepted by the Admission Committee as per the following criteria:

- (i) 70% weightage will be given to the marks obtained in the written entrance test;
- (ii) 30% weightage will be given to interview.

For candidates exempted from the written entrance test, the merit list of candidates whose research proposals are accepted by the Admission Committee will be prepared on the basis of points listed at clause 3.13 (ii) above, scaled up to 100 marks.

- 3.14 The allocation of a research supervisor for a selected research scholar shall be decided by the Admission Committee depending on the number of scholars per research supervisor, the available specialization among the supervisors and the research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview. The allocation of seats shall be based on merit and reservation policy.
- 3.15 The Admission Committee shall propose the final merit list of the selected candidates based on PET and/or interview to the concerned SRC for its consideration and approval. After the approval of the SRC of the concerned discipline, it shall be displayed on the University website by the concerned USS, and all the admission formalities thereafter

shall be completed by the Admission Committee. Subsequently, the list of admitted candidates shall be sent to RDC for the issue of enrollment numbers.

- 3.16 The admission to the Ph.D. programme shall be allowed in Full time/ Part time mode. The concerned SRC shall decide whether both or only one mode of admission in a particular discipline shall be allowed. The information shall be communicated to the RDC for incorporation in the admission brochure.
- 3.17 Employed candidates including permanent faculty members of the University Schools or affiliated colleges/institutions, who wish to seek Ph.D. admission as full-time research scholars, must obtain leave for a period of at least three years to fulfill the minimum registration period of the University. Candidates who need proof of selection to obtain leave from their employers may use the selection/admission list displayed on the University website for this purpose, but admission shall only be granted upon submission of the leave sanction letter in original.
- 3.18 All employed candidates (full-time/part-time), in regular employment must submit a “No Objection Certificate” from the appropriate authority in the organization where the candidate is employed for the purpose of pursuing Ph.D. programme. The “No Objection Certificate” should clearly state that:
- The candidate is permitted to pursue studies on a full-time/part-time basis.
  - His/her official duties permit him/her to devote sufficient time for research.
  - If required, he/she will be relieved from the duty to complete the coursework.

The “No Objection Certificate” must be submitted to the Ph.D. Admission Committee at the time of interview for admission.

- 3.19 All personnel(s) working in research projects in GGSIP University can pursue a full-time Ph.D. in GGSIP University, subject to their fulfilling the eligibility conditions for admission to the Ph.D. programme of GGSIP University. However, they will have to submit a "No Objection Certificate" from the respective Principal Investigator (PI) of the research project in which they are working for the purpose of pursuing a Ph.D. programme, and the same must be submitted at the time of interview for admission.
- 3.20 The Admission Committee may decide not to fill all/any of the advertised seats/slots in a particular discipline notified in the admission brochure.
- 3.21 The RDC of the University shall maintain the list of all the Ph.D. registered students on its website on a year-wise basis. The list shall include the name of the registered candidate, the area of his / her research, name of his / her supervisor/co-supervisor, date of enrolment/registration.

#### **4.0 Duration (Registration Period) of the Ph.D. Programme**

- 4.1 Ph.D. programme shall be for a minimum duration of three (3) years, including course work and a maximum duration of six years, from the date of admission to the Ph.D. programme.
- 4.2 A maximum of an additional two (2) years can be given through a process of re-registration, which shall require approval of extension by the concerned SRC, and

payment of fee as applicable at the time of admission of the research scholar into the Ph.D. programme, as well as Rs 1000/- as re-registration fee. This extension may be granted by the SRC of the concerned school on a written request by the research scholar and recommendation of the Research Advisory Committee (Constitution of the RAC shall be as per clause 8.1 of this Ordinance). The request for extension by the research scholar should specify the reasons for the extension sought and should be recommended by the supervisor for the consideration of the SRC. The SRC for reasons recorded in writing may consider and approve the extension. Provided, however, that the total period for completion of a Ph.D. programme should not exceed eight (8) years from the date of admission in the Ph.D. programme.

- 4.3 Female research scholars and Persons with Disability (more than 40% disability) shall be allowed an additional relaxation of two (2) years. This extension may be granted by the SRC of the concerned school on a written request by the research scholar and recommendation of the Research Advisory Committee. However, the total period for completion of a Ph.D. programme in such cases should not exceed ten (10) years from the date of admission in the Ph.D. programme.
- 4.4 Female Ph.D. Scholars may be provided Maternity Leave/Child Care Leave for up to 240 days in the entire duration of the Ph.D. programme, and this period shall be counted for the calculation of the registration period.
- 4.5 If the research scholar is not able to submit his / her thesis within the stipulated period, his / her registration/admission shall stand cancelled.

#### 4.6 **Leave / Absence for Full-time Research Scholars**

- 4.6.1 Every registered research scholar shall report on a day-to-day basis to his/her supervisor, who shall decide whether the research scholar is required to work within or outside the School/University or undertake outstation field work as needed. Such period of absence, including participation in seminars/workshops/conferences/symposia etc., shall be regarded as 'on duty' and not on leave. However, research 'on duty' outside the University for periods exceeding one month at one time in an academic year shall require the prior written recommendation of the supervisor, approval of the RAC, and due intimation to the Dean of the School, subject to the ratification in the next SRC meeting.
- 4.6.2 During the entire tenure of a Ph.D., research work 'on duty' outside the University shall ordinarily be limited to a period of 24 months for field work and 12 months for working at the institution of the co-supervisor or any other place assigned by the RAC. Any further extension may be considered for approval by the SRC on the recommendation of the RAC (with justification for extension).
- 4.6.3 The supervisor may grant leave of not more than Five (5) working days at one time out of the total leave due to the research scholar as defined by the fellowship-funding agency or the University (30 days in one calendar year) as applicable. Any leave beyond Five (5) working days would require prior written application by the research scholar, duly forwarded/recommended by the supervisor, to the Dean of the School for approval. All such cases will be subsequently reported to the RAC and SRC. The leave period shall be counted in the total period required for submission of the thesis as stipulated in this Ordinance.
- 4.6.4 The supervisor must report absence from research work by research scholars due to

illness, maternity leave or other circumstances to the SRC through RAC and the Dean of the School. Cases of neglect of research work and indiscipline that include unethical practices such as unauthorized absence, plagiarism and misrepresentation of data and irregularity must be recorded and reported by the supervisor to the RAC. RAC shall consider& make appropriate recommendations to the SRC for its consideration. The SRC shall consider the recommendations of the RAC and any other relevant factor, may take appropriate action, including cancellation of his/her admission, however, no decision shall be made without giving reasonable opportunity to the scholar to present his/her case.

- 4.6.5 All the leave records of the research scholars are to be maintained by the concerned supervisor.

#### **4.7 Cancellation / Termination of Registration**

- 4.7.1 The registration of a research scholar may be cancelled/ terminated under the following circumstances:

- (i) If he/she remains absent for a continuous period of two weeks without prior intimation/sanction of leave with the recommendation of the supervisor, applicable to full-time scholars.
- (ii) If he/she resigns from the Ph.D. programme and the resignation is duly recommended by the supervisor and accepted by the SRC.
- (iii) If he/she fails to renew his/her registration by not paying the requisite fee in the specified period.
- (iv) If he/she is found to be involved in an act of misconduct and/or indiscipline and termination is recommended by the RAC and approved by the SRC, or any other statutory official/body authorized by the University.
- (v) If he/she fails in the course work as per the provisions of this Ordinance within the stipulated period.
- (vi) If he/she fails to make research progress to the satisfaction of the RAC despite a second warning as defined in clause 8 below.
- (vii) If he/she fails to complete the requirement for the award of the degree in the stipulated period.
- (viii) If he/she fails to submit two consecutive six monthly reports to the Research Advisory Committee.
- (ix) As per clauses specified elsewhere in this Ordinance.

- 4.7.2 Termination order of a research scholar for any reason as outlined in 4.7.1 above shall be recommended by the Research Advisory Committee and approved by the concerned SRC. The order shall be issued by the Dean of the concerned School and forwarded to the RDC for record purpose.

#### **5.0 Research Supervisors: Eligibility criteria to be a Supervisor, Co-Supervisor, Number of Ph.D. Scholars permissible per Supervisor, etc.**

- 5.1 Permanent faculty members working as Professor/Associate Professor of the USS / Affiliated College with a Ph.D., and at least five research publications in peer-reviewed or refereed journals and permanent faculty members working as Assistant Professors in USS / Affiliated College with a Ph.D., and at least three research publications in peer-reviewed or refereed journals may be recognized as a Research Supervisor in the University where the faculty member is employed or in its affiliated Post-graduate Colleges/institutes. Such recognized research supervisors cannot supervise research

scholars in other institutions, where they can only act as co-supervisors. Adjunct Faculty members shall not act as Research Supervisors and can act only as co-supervisors.

However, the University School of Medicine & Para-Medical Health Sciences, any recognized teacher of the University Affiliated Medical Colleges who holds an MD / MS / DM / M.Ch. or equivalent degree (and not holding a Ph.D. degree) with 15 years of teaching and research experience after obtaining MD / MS / DM / M.Ch. or equivalent degree, including PG teaching experience of 10 years as a faculty member and 10 published research articles in indexed peer review journals, and is continuously involved in research activities, shall be eligible to be recognized as a Ph.D. Supervisor, subject to the fulfillment of other conditions specified in this Ordinance.

- 5.2 A recognized supervisor can become the sole supervisor of a scholar if at least 03 years are remaining till the superannuation of the supervisor. For the last 03 years of service till superannuation, an additional recognized Co-supervisor with adequate service left shall be necessary and the Co-supervisor shall be appointed by the concerned SRC. However, if the thesis has been submitted, but the viva-voce has not been held or the degree has not been awarded, there shall be no need of a co-supervisor. However, if the thesis after evaluation by external examiners is returned for revision, then the SRC may appoint a Co-supervisor/ Caretaker supervisor. Faculty members with less than three years of service before superannuation shall not be allowed to take new research scholars under their supervision. However, such faculty members can continue to supervise Ph.D. scholars who are already registered until superannuation and as a co-supervisor after superannuation, but not after attaining the age of 70 years.
- 5.3 Co-supervisor(s) can be allowed in inter-disciplinary areas from other University Schools/ Centre(s) of the University / affiliated college / other Central/ State Universities/Institutions, provided such persons fulfill the academic requirement for being recognized as a supervisor as per this Ordinance. The terms and conditions for the appointment of Co-supervisors shall be specified by the Research Advisory Committee and the Co-supervisor will have to be approved by the concerned SRC of the parent School/Centre of the faculty and Competent Authority. The same shall be communicated to RDC.
- 5.4 A supervisor may be recognized in more than one discipline. A recognized supervisor, irrespective of the fact that he/she belongs to USS/Affiliated College allowed to offer a Ph.D. programme, shall be a member of the SRC governing the said discipline. A faculty member of USS may be recognized as a supervisor in a different USS/Centre with the approval of the SRC of his/her parent School/Centre and the approval of the Competent Authority. The concerned faculty may have both teaching and research responsibilities in all School/Centre where he/she is a recognized Supervisor.
- 5.5 A Research Supervisor / Co-Supervisor who is a Professor, at any given point of time, cannot guide more than Eight (08) Ph.D. scholars. An Associate Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of six (06) Ph.D. scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of four (04) Ph.D. scholars. In case of joint supervision, the number of research scholars enrolled will be counted as one for each of the joint supervisors.
- 5.6 If a co-supervisor is allotted from out of this University (or its affiliated colleges), or if a faculty of USS/Centre is involved as a supervisor/co-supervisor in any other USS/Centre beside his/her parent USS/Centre or in any other University/institution, it is mandatory that he/she informs the number of such research scholars to the SRC, as they shall be

counted towards the calculation of the permissible/available slots for Ph.D. as per this ordinance. Any failure in intimating this to the concerned SRC may lead to misconduct and suitable action may be recommended. Once a registered research scholar submits his/her Ph.D. thesis for evaluation purpose, Ph.D. slot/seat will be counted as vacant for a recognized supervisor once the thesis is submitted for evaluation purposes in the office of the Director/Dean of the concerned School/Centre after a pre-submission presentation by the Ph.D. research scholar.

- 5.7 A full-time regular teacher, on fulfilling the requirements to be recognized as a Supervisor shall apply to the concerned SRC. The Director, RDC on the recommendation of the SRC, and after obtaining approval from the Vice-Chancellor, shall issue the notification regarding the recognition of teacher as a Supervisor. The form for such recognition shall be made available on the University website by the RDC. The list of recognized supervisors shall be displayed on the University website by the RDC.
- 5.8 In case(s), where a supervisor retires, resigns, proceeds on leave/deputation exceeding one year, expires, or any other unforeseen circumstances necessitate redistribution/re-allotment of a research scholar, the SRC shall allot supervisor(s)/co-supervisor(s)/caretaker supervisor, ideally from the same School/institution/discipline as supernumerary allotment, and inform the RDC. In case(s) wherein SRC is unable to identify a supervisor in the discipline recognized by the University, the scholar shall be allowed to choose any person satisfying the academic criterion required to be recognized as a supervisor, subject to the approval of the SRC through RDC and the Vice-Chancellor.
- 5.9 Recognized supervisors who have been sanctioned or have proceeded on deputation/lien/long leave of a year (or more) (at the time of the interview for Ph.D. admission or allotment of supervisor) may not be allotted a research scholar in that academic session.
- 5.10 A research scholar may request in writing for a change of supervisor(s) with proper justification, through the Dean of the concerned School to the respective SRC. The SRC after considering the circumstances of such a request may approve a change of supervisor(s) with the approval of the Competent Authority under intimation to the RDC for the record.
- 5.11 In case of relocation of a female Ph.D. scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the university to which the scholar intends to relocate, provided all the other conditions in these Regulations are followed, and the research work does not pertain to a project sanctioned to the parent Institution/Supervisor by any funding agency. The such scholar shall, however, give due credit to the parent institution and the supervisor for the part of research already undertaken.

## **6.0 Admission of International Students in the Ph.D. programme**

- 6.1 Each supervisor can guide up to two international research scholars on a supernumerary basis over and above the permitted number of Ph.D. scholars as specified in clause 5.5 above.
- 6.2 The modalities of Ph.D. admission of international students shall be notified separately

by the Directorate of International Affairs of the University with the approval of the Director, RDC and Vice-Chancellor. The detailed procedure shall be proposed by the Directorate of International Affairs in consonance with this Ordinance, and shall be notified as Regulation after the approval of the Academic Council.

- 6.3 At any point, the total number of Ph.D. scholars under a faculty member, either as a supervisor or a co-supervisor, shall not exceed the number prescribed in clause 5.5 and clause 6.1 above.

**7.0 Course Work: Credit Requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc.**

- 7.1 The Credit requirement for the Ph.D. coursework shall be a minimum of 12 credits, including a "Research and Publication Ethics" course as notified by UGC vide D.O. No. F.1- 1/2018(Journal/CARE) in 2019 and a research methodology course. The Research Advisory Committee can also recommend UGC-recognized online courses as part of the credit requirements for the Ph.D. programme.
- 7.2 The medium of instruction of coursework shall be English unless approved otherwise for reasons recorded in writing by the concerned SRC at the time of admission/registration, as per the specified format and instructions.
- 7.3 The detailed coursework for Ph.D. shall be designed and recommended by the concerned SRC and approved by the concerned BOS and Academic Council.
- 7.4 All courses prescribed for Ph.D. coursework shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods.
- 7.5 The SRC governing the discipline in which the scholar pursues his/her research shall prescribe the course(s) to him/her based on the recommendations of the Research Advisory Committee of the research scholar. All Ph.D. scholars, irrespective of discipline, shall be required to train in teaching /education /pedagogy/writing related to their chosen Ph.D. subject during their doctoral period. Ph.D. scholars may also be assigned 4-6 hours per week of teaching/research assistantship for conducting tutorial or laboratory work and evaluations.
- 7.6 All candidates admitted to the Ph.D. programme(s) shall be required to complete the coursework prescribed by the SRC during the initial one or two semesters. The maximum period for completion of the course work shall be two years from the academic session in which the scholar is admitted. If a scholar fails in any course/paper, the scholar shall reappear as and when the course/paper examination is scheduled subsequently.
- 7.7 Candidates already holding M.Phil. degree and admitted to the Ph.D. programme, may be exempted by the SRC from the Ph.D. coursework. All other candidates admitted to the Ph.D. programme shall be required to complete the Ph.D. coursework prescribed by the SRC. The coursework already completed by the scholar, seeking exemption from the coursework of the Ph.D. programme, must be in consonance with the coursework guidelines specified in this Ordinance. The exemption provided to a candidate from Ph.D. coursework shall be documented in writing by the SRC in the first year of admission of the student.

- 7.8 The grading system and divisions for the course work shall be as specified in the Ordinance 11 of the University. Each paper/course of the course work shall be of maximum of 100 marks. The Teacher's Continuous Evaluation component shall be of 25 marks and the End-Term Semester Examination component shall be of 75 marks.
- 7.9 Attendance requirement in the course work shall be of minimum 75% of the classes held, the SRC may condone up to 5% of the attendance in specific instances, with reasons recorded in writing. Under no circumstances, a scholar with less than 70% attendance in the course shall be allowed to appear in the End-Term Semester Examination by the SRC. The list of detained (not allowed to appear in examinations) scholars shall be notified at least 5 working days before the commencement of end-term examinations, by the chairperson of the SRC with a copy to the Controller of Examinations for non-issuance of admit card.
- 7.10 The teacher's continuation evaluation of 25 marks, for every course shall be conducted by the concerned faculty who is allocated the responsibility of teaching the course by the SRC. The concerned faculty shall communicate their marks to the Controller of Examinations through the Dean, within a week of the completion of the semester.

For the rest 75 marks, the Controller of Examinations shall conduct the examination. The panel of paper setter, as approved by the BOS shall be communicated to the Controller of Examinations. The Controller of Examinations shall declare the result combining the teacher's continuation evaluation and the end-term semester examination. The duration of the semester shall be of 15 weeks. No other mode of examination shall be permitted for any paper/course.

- 7.11 A Ph.D. scholar must obtain a minimum of 55% marks or its equivalent grade in the UGC 10-point scale in the course work to be eligible to continue in the programme and submit his or her thesis. If a scholar does not obtain the minimum grade, the scholar may reappear in one or more course work paper/courses to improve the grade. The reappear fee applicable shall be as notified for other examinations of the University. If the minimum grade required is not obtained in the maximum duration for the course work as specified, the registration/admission of the scholar shall be automatically cancelled. The Dean/Director of USS/Centre shall intimate the same to the RDC for the updation of records.

## **8.0 Research Advisory Committee and its Functions**

- 8.1 There shall be a Research Advisory Committee (RAC) for every scholar admitted in the School. The RAC shall comprise a minimum of 5 members. The minimum composition of RAC shall be as follows:
- (a) One Professor of the School who is also a member of the SRC - *Chairperson*
  - (b) Two/Three recognized supervisors, other than the supervisor of the scholar, recognized as supervisors preferably in the same SRC – *members*
  - (c) Co-Supervisor (if any) of the scholar – *member*
  - (d) Supervisor of the scholar – *member convener*

The members of the RAC shall be proposed by the supervisor for consideration and approval of the SRC of the concerned USS/Centre. External subject experts from outside the University may be co-opted if needed with the approval of the SRC. The Research Supervisor of the scholar shall be the Convener of this Committee.

This Committee shall have the following responsibilities:

- 8.1.1 To review the research proposal and finalize the topic of research. The synopsis of the research work of the scholar shall be finalized within 12 months of a Ph.D. programme from the date of admission in the programme. The finalized synopsis shall be forwarded for the approval of the SRC and sent to RDC for records. Non-finalization of the synopsis in the stipulated period shall lead to the cancellation of the admission of the scholar.
- 8.1.2 To guide the research scholar to develop the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she may have to do from among the courses prescribed under clause 7 above.
- 8.1.3 To periodically review and assist in the progress of the research work of the research scholar. The assessment/recommendation of the RAC shall be submitted to the concerned SRC for further necessary action.
- 8.1.4 The academic research progress of each research scholar shall be monitored by the concerned RAC at a 6-monthly interval, based on the written progress report and oral presentation by the research scholar. Failure to submit a timely progress report and/or make a presentation to the RAC shall be construed as indiscipline and treated accordingly. The progress reports of all registered research scholars shall be placed before the SRC, duly forwarded by their supervisors after the meeting of the RAC, with the RAC's comments on whether the progress of the research scholar was good/satisfactory/poor. The SRC, after having considered the progress report and the comments of the RAC, shall recommend one of the following:
  - (i) Continuation of registration.
  - (ii) Continuation of registration with a written warning to the research scholar, which may include the steps necessary to improve his/her performance, identified in consultation with the supervisor(s). The second and final warning shall include the extension of the minimum registration period for thesis submission by one year.
  - (iii) Termination of registration, if the research scholar still fails to make progress to the satisfaction of the RAC and the SRC despite the second and final warning.
- 8.2 A research scholar shall appear before the Research Advisory Committee once in six months to make a presentation and submit a brief report on the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The six monthly progress reports shall be submitted by the Research Advisory Committee to the concerned SRC with a copy to the research scholar. The SRC shall send a consolidated summary report to the RDC for all the scholars registered in the School for information and records, concerning, the progress of the scholars. The convenor of the Research Advisory Committee shall ensure that at least one meeting of the RAC shall be conducted every six months.
- 8.3 In case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the research scholar fails to implement these corrective measures, the Research Advisory Committee may recommend to the concerned SRC with specific reasons for the cancellation of the registration of the research scholar.

## **9.0 Evaluation and Assessment Methods, minimum standards/ credits for award of the**

**degree, etc.**

- 9.1 The Ph.D. scholar shall be required to undertake research work and produce a draft thesis within a reasonable time, as stipulated in this Scheme of Examination and Syllabi of the Ph.D. programme and in consonance with this Ordinance, together with successful completion of coursework and obtaining the marks/grade prescribed in the clause 7 above.
- 9.2 Ph.D. scholars must publish (or paper accepted) at least one (1) research paper in Scopus/Web of Science indexed journals before the submission of the thesis for adjudication, and produce evidence for the same. However, in the case of schools/disciplines other than Sciences/Engineering/Technology /Management, where there is no, or only a limited number of Scopus/Web of Science indexed journals, the SRC of the concerned discipline may relax the above condition with reasons recorded in writing. However, in such cases, the publication must at least be in peer-reviewed journals (with ISSN). However, the SRC of a concerned discipline may make a higher criterion for paper publication during the Ph.D. work.
- 9.3 On completion of the research work, the research scholar shall submit 08 copies of the pre-submission synopsis of his/her Ph.D. thesis through the supervisor to the Research Advisory Committee, and make a pre-submission presentation to the Research Advisory Committee. The pre-submission presentation shall also be open to all faculty members and other research scholars of the University. The feedback and comments obtained from them may be suitably incorporated into the draft thesis in consultation with the Research Advisory Committee. The decision of the RAC after the pre-submission presentation allowing/disallowing the submission of Ph.D. thesis shall be placed before the concerned SRC for its information.
- 9.4 The research scholar shall submit his/her thesis within three months from the date of approval of the pre-submission presentation by the RAC. However, in case a research scholar fails to submit his/her thesis within the stipulated time and has suitable justification for the same, the Dean of the School may, on the recommendations of the SRC (or subject to SRC approval, as appropriate), grant an extension of not more than three months. In other words, the research scholar may be allowed to submit his thesis within 06 months from the date of RAC's approval of the pre-submission presentation. If a research scholar fails to submit his/her thesis within 06 months of his/her pre-submission presentation, he/she will have to make a fresh presentation before the RAC.
- 9.5 The final title of the thesis shall be approved by the RAC in the pre-submission presentation of the scholar.
- 9.6 The thesis shall be written in English unless approved otherwise for reasons recorded in writing by the concerned RAC and approved by the SRC within one year of admission/registration, as per the specified format and instructions. The format of the thesis shall be specified by the RDC with the approval of the Vice-Chancellor, and shall be made available on the University website.
- 9.7 All research scholars are expected to follow ethical practices in their research work. For the prevention of plagiarism as well as other forms of academic dishonesty in research work, all scholars & supervisors shall follow the University Regulations titled "GGSIPU Academic Research and Ethics Regulation,2022"available on the University website (<http://www.ipu.ac.in/Pubinfo2020/nt655210820.pdf>).

- 9.8 A Ph.D. scholar shall submit the thesis for evaluation, along with (a) an undertaking from the Ph.D. scholar that there is no plagiarism and (b) a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the thesis and that the thesis has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the University or to any other Institution.
- 9.9 The Ph.D. thesis submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least two external examiners, who are experts in the field and, who are not in employment of the University or any of its Affiliated Institutions. Such examiners should be academics with a good record of scholarly publications in the field. The viva-voce examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by the 'Oral Defence Committee' as defined in clause 9.12.2 below, and shall be open to be attended by members of the Research Advisory Committee, all faculty members of the School, all recognized supervisors of the University, other research scholars and other interested experts/ researchers and students.

#### **9.10 Appointment of Examiners for Ph.D. Thesis**

- 9.10.1 For the purpose of evaluation of Ph.D. thesis, the recognized supervisor of the concerned USS/Centre shall submit a list of at least 8-10 experts in the subject area of research work, not below the rank of Associate Professor, including at least 4-5 experts from outside the state/country for the approval of the SRC of the concerned discipline. These experts should possess requisite qualifications equivalent to the requirement for recognition of a supervisor in GGSIPU. They should be recognized as Ph.D. supervisors in any University recognized by UGC or serving or retired in national research & technology institutions established by the Government. Only one examiner may be provided from an institution. The SRC may add or delete any of the names(s) proposed by the supervisors(s). The supervisor shall be responsible to provide the full contact details of each of the examiners, including postal address, email, phone, fax, etc.
- 9.10.2 An examiner cannot be from the same institution where the research scholar is employed, or from the institution to which the supervisor and/or Co-supervisor of the research scholar belongs. Further, a collaborator or co-author of the research scholar or his/her supervisor or Co-supervisor during the tenure of the concerned Ph.D. research scholar cannot be an examiner. The responsibility for ensuring this shall lie on the Supervisor / Co-Supervisor of the scholar. In case, it is found the supervisor / Co-supervisors have not maintained this standard of academic ethics, the SRC may recommend for debarment of the concerned supervisor/co-supervisor for further registration of scholars for a minimum period of three years to the Vice-Chancellor. The decision of the Vice-Chancellor shall be final.
- 9.10.3 On receipt of the final title and pre-submission synopsis of the thesis approved by the SRC, the Chairperson of the SRC shall send the panel of examiners as approved by the concerned SRC as well as the pre-submission synopsis to the COE within a week of receiving the said documents. The Vice-Chancellor shall appoint the external thesis evaluator(s) from the above panel for evaluation of the thesis. The Vice-Chancellor may add names to the panel of examiners.
- 9.10.4 The Examination Division will follow the modalities for the evaluation of the Ph.D. thesis as approved by the Vice-Chancellor.

### **9.11 Evaluation of the Ph.D. thesis**

- 9.11.1 Each examiner will be requested to submit to the COE, a detailed assessment report and his/her recommendations on a prescribed proforma (designed by the Examinations Division and approved by the Controller of Examinations) within 06 weeks from the date of receipt of the thesis.
- 9.11.2 In the event that the assessment report is not received from an examiner within 3 months from the date of dispatch of the thesis, the Vice Chancellor may appoint another examiner from the approved panel of examiners for evaluating the Ph.D. thesis.
- 9.11.3 The examiner shall be required to state categorically whether in his opinion, the Ph.D. thesis should be:
- (a) accepted for the award of Ph.D. degree (after oral defence), or
  - (b) accepted for the award of Ph.D. degree (subject to incorporation of changes suggested and after oral defence), or
  - (c) resubmission in the revised form, or
  - (d) rejected
- 9.11.4 The examiner shall state the reasons for recommending resubmission/rejection of the Ph.D. thesis. If a resubmission is recommended, the examiner shall specifically indicate the modifications that need to be made in the Ph.D. thesis by the research scholar. The COE in consultation with the Dean of the School shall also provide to the research scholar and supervisor, a list of all corrections and modifications required in the thesis, as suggested by the examiners.
- 9.11.5 If the corrections are major and resubmission/re-evaluation has been recommended, the research scholar may resubmit the revised version in consultation with the supervisor, within a period of one year from the date of communication in this regard from the COE. However, in exceptional circumstances, this period may be extended by SRC by one more year but the total revision time shall not exceed two years. The revised Ph.D. thesis shall be sent for assessment to the same examiner(s) who recommended the revision. In the event of any of them declining to examine the revised thesis, an additional examiner may be appointed from the approved panel, and provided with the comments of the previous examiner(s) to facilitate the evaluation of the revised thesis.

### **9.12 Oral Defence / Viva-Voce**

- 9.12.1 The oral defence/ viva-voce of the Ph.D. research scholar to defend the Ph.D. thesis shall be conducted only if the evaluation report(s) of both the external examiner(s) on the thesis are satisfactory and include a specific recommendation for acceptance of the thesis and conducting the viva-voce examination. In case, the Ph.D. thesis is rejected by both the external examiners, then the thesis shall stand rejected without any further action and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree. If one of the evaluation reports of the external examiner in case of Ph.D. thesis, is unsatisfactory and does not recommend viva-voce, the examination branch of the University shall send the thesis to an alternate external examiner out of the approved panel of examiners and the viva-voce examination shall be held only if the report of the alternate examiner is satisfactory and if the alternate examiner recommends

acceptance of the thesis. If the report of the alternate examiner is also unsatisfactory and does not recommend acceptance of the thesis, the thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree. The examination branch of the University shall complete the entire process of evaluating a Ph.D. thesis, including the declaration of the viva-voce result, within a period of six (6) months from the date of submission of the thesis.

9.12.2 A research scholar, after receiving a satisfactory Ph.D. thesis evaluation report, shall be required to defend his/her work/thesis orally before a duly constituted committee, herein after referred to as Oral Defence Committee (ODC).

9.12.3 ODC shall consist of the Chairperson of the RAC of the concerned scholar, supervisor(s) (at least one must be present), and one external examiner who evaluated the thesis to be appointed by the Vice-Chancellor. If none of the examiners who evaluated the thesis is available for the conduct of the oral defence, an alternative examiner from the panel of approved examiners shall be appointed by Vice-Chancellor.

9.12.4 The Open Viva Voce and the defence by the research scholar may also be done through Skype/Video conferencing, if required, with prior approval of the Vice Chancellor.

9.12.5 On completion of all the stages of examination culminating with the Viva Voce, the ODC shall submit its report in the prescribed proforma (designed by the Examinations Division and approved by the Controller of Examinations) to the Vice Chancellor through the COE recommending any one of the following:

- (i) that the degree be awarded,
- (ii) that the research scholar be subjected to a fresh Oral Defence at a later date,
- (iii) that the degree be not awarded.

9.12.6 The decision of the Vice Chancellor on the recommendations of the ODC shall be notified by the COE, mentioning the date of the decision of the Vice Chancellor, which shall be construed as the effective date of the award of the Ph.D. degree, subject to the formal award during the University convocation. Prior to this notification, the COE shall ensure that the research scholar has submitted a soft copy of the Ph.D. thesis and two hard-bound copies, one for the library of the concerned School and one for the central library of the University. These should incorporate all necessary corrections/modifications certified by the supervisor and must contain the following copyright certificate in the beginning of the thesis, on a separate page:

**©Guru Gobind Singh Indraprastha University, Dwarka, New Delhi-110078. All rights reserved**

9.12.7 The University may issue a Provisional Certificate of the completion of Ph.D. to the research scholar upon Ph.D. notification, followed by the award of the final degree at the time of convocation, along with a certificate to the effect that the Ph.D. degree has been awarded in accordance with the UGC regulations. The certificate and the degree shall mention the School, the Institution of Study and the discipline in which the Ph.D. degree is awarded.

**10.0 Academic, research, administrative and infrastructure requirements to be fulfilled by Affiliated Colleges for getting recognition for offering Ph.D. programmes**

- 10.1 Affiliated Colleges may be considered eligible to offer Ph.D. programmes only if they satisfy the availability of eligible Research Supervisors, required infrastructure and supporting administrative and research promotion facilities as per this Ordinance.
- 10.2 The Affiliated College should at least be in existence with an uninterrupted and continual functional status of 5 years or more and should be offering 4-year Undergraduate programmes and/or Post-graduate programmes, with at least two Ph.D. qualified teachers/other academic staff (scientists) in the discipline concerned along with required infrastructure, supporting administrative and research promotion facilities as per this Ordinance, stipulated under sub-clause 10.3, shall be considered eligible to offer Ph.D. programmes only in the disciplines having PG programmes/ 4-year undergraduate programmes. Affiliated Colleges should obtain the necessary recognition by the University to offer Ph.D. programme.
- 10.3 Departments of Affiliated Colleges with adequate facilities for research as mentioned below, shall be allowed to offer Ph.D. programmes:
- 10.3.1 In case of science and technology disciplines, exclusive research laboratories with sophisticated equipment as specified by the Institution concerned with provision for adequate space per research scholar along with computer facilities and essential software, and uninterrupted power and water supply;
- 10.3.2 Earmarked library resources including latest books, Indian and International journals, e-journals, extended working hours for all disciplines, adequate space for research scholars in the Department/ library for reading, writing and storing study and research materials;
- 10.3.3 Affiliated Colleges shall apply to the Director, RDC for the purpose of recognition to offer Ph.D. programmes in specific disciplines. The application format for application by any college for consideration to offer a Ph.D. programme shall be proposed by the Director, RDC and approved by the Vice-Chancellor. The Director, RDC after the approval of the Vice-Chancellor shall notify the application form on the University website.
- 10.3.4 Such Affiliated Colleges shall be permitted to offer Ph.D. programmes only after receiving a satisfactory report from an experts committee constituted by the Vice Chancellor for the purpose of visiting the Affiliated College and to evaluate the infrastructure and other facilities needed to start a Ph.D. programme.
- 10.3.5 The SRC of the concerned USS shall decide the specific discipline(s) in which the Ph.D. programme may be offered and shall specify detailed requirements as per clause 10.3.1 and 10.3.2, for consideration of the application of any college to be considered for offering Ph.D. programme and fulfillment of other requirements as specified in this Ordinance.
- 10.3.6 The Director, RDC after the approval of the Vice-Chancellor may also notify other requisite eligibility criteria for the Affiliated Colleges.
- 10.4 The Affiliated college should also have regular and qualified staff to the satisfaction of the University. Of the teaching staff of the Affiliated College, those who meet the eligibility qualifications and experience as per provisions of this Ordinance shall be approved as "Supervisors" by the SRC of the concerned USS as per the procedure

prescribed in clause 5 of this Ordinance.

- 10.5 The process for admission of research scholars in a particular discipline in the Affiliated College shall be completed through the Admission Committee constituted at the level of USS/Centre. For a 4-year degree programme in a particular discipline or PG programme in a particular discipline, if Ph.D. is offered at an Affiliated College, then the SRC of the concerned USS shall act as the SRC of the discipline for the particular Affiliated College. If any agenda/item connected to a particular research scholar admitted in the Affiliated College is considered/ discussed by the SRC, then the supervisor of the research scholar shall be invited to the meeting of the SRC.
- 10.6 A Research Advisory Committee (RAC) shall be constituted in the Affiliated College for every scholar admitted in the Affiliated College, with similar composition and functions as defined in clause 8 of this Ordinance. The members of the RAC shall be approved supervisors in the Affiliated College. However, the Chairperson of the RAC shall be a member of the SRC of the concerned USS.
- 10.7 The research scholar shall complete coursework and all other formalities in accordance with the provisions of this Ordinance.
- 10.8 On completion of the research work, the research scholar shall submit 08 copies of the pre-submission synopsis of his/her Ph.D. thesis through the supervisor and the Research Advisory Committee to the SRC of the concerned USS. The pre-submission of such scholars should be made before a committee of the SRC of the concerned USS, chairperson of RAC, RAC members and the supervisor of the concerned research scholar.
- 10.9 The University shall not entertain any request for Ph.D. programmes for which the University does not have an SRC.
- 10.10 There shall be no application/continuation fee for the Affiliated Colleges. The Colleges thus recognized cannot charge any extra fee from the Research Scholars other than those prescribed from time to time by GGSIP University i.e., registration, annual fee, course fee and thesis submission fee.
- 10.11 On the lines of GGSIP fellowships, the Affiliated Colleges may also offer their own Research Fellowships to research scholars with a view to generate warranted research environment at their Colleges.
- 10.12 Each of the scholar admitted at any of these Affiliated Colleges shall be required to pay fee, etc. to the University separately as may be prescribed by the University from time to time.
- 10.13 All such Affiliated Colleges shall function in accordance with the applicable University Act, University's Ordinance governing programmes leading to the degree of Doctor of Philosophy, rules & regulations of the University, guidelines & directions issued by the concerned School Research Committee as well as the Director, RDC, and shall be applicable on all the research scholars of these Affiliated Colleges in totality.

#### **11.0 Ph.D. through Part-time Mode**

- 11.1 Ph.D. Programmes shall not be offered through distance and or online education mode.
- 11.2 Part-time Ph.D. shall be allowed only for employed candidates provided all the conditions mentioned in this Ordinance are met. Conversion of full-time registration into part-time registration and part-time to full-time registration shall be allowed during the Ph.D. tenure on a case-to-case basis with reasons recorded in writing by the SRC of the concerned School upon recommendations of the RAC. The decision of the SRC should be communicated to the RDC for record purposes.
- 11.3 The University shall obtain a “No Objection Certificate” through the candidate for a part-time Ph.D. programme from the appropriate authority in the organization where the candidate is employed, clearly stating that:
- The candidate is permitted to pursue studies on a part-time basis.
  - His/her official duties permit him/her to devote sufficient time for research.
  - If required, he/she will be relieved from the duty to complete the coursework.
- 11.4 The course work shall be offered to the part-time scholars. The part-time scholars shall have to fulfil the coursework requirement as per the provisions of this Ordinance.

#### **12.0 Depository with INFLIBNET**

Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. degree(s), the Examination Division shall provide an electronic copy of the Ph.D. thesis to the library of the University. The Librarian of the University Library shall ensure the submission of the said copy to the INFLIBNET in accordance with the Consent Form for Depository with Shodhganga or INFLIBNET or any other database designated for this purpose by the University Grants Commission in the prescribed format.

#### **13.0 Issuing a Provisional Certificate**

Prior to the actual award of the degree, the Examination Division of the University shall issue a provisional Certificate to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions of the applicable UGC Regulations.

#### **14.0 Consideration of already registered scholars who have not submitted their thesis**

The Ordinance applicable at the time of admission of the already registered scholar shall apply.

- 15.0 The eligibility of the supervisors recognised by the University before the enactment of this ordinance shall be reviewed by the concerned SRC.
- 16.0 For supervisors belonging to affiliated colleges, first the affiliated college have to be approved as institutions offering Ph.D. programmes as per the clauses of this Ordinance. Pending the same, the supervisors of the affiliated colleges shall not be allowed to register new scholars under their supervision; this shall have no effect on their supervision of scholars registered before the enactment of this Ordinance. Operational guidelines for the recognition of supervisors shall be issued by the RDC after approval of the Vice-Chancellor.

- 17.0 The admission fee, the annual continuation fee, and the thesis submission fee shall be notified by the University.
- 18.0 Provisions for financial assistance (if any) to eligible full-time research scholars admitted to USS only under the supervision of recognized supervisors who are in regular full-time employment of the University, shall be notified by the University.
- 19.0 Operational guidelines for the preparation of the admission brochure and its issuance shall be proposed by the Director, RDC and implemented after approval of the Vice-Chancellor.
- 20.0 Operational guidelines for evaluation of the Ph.D. thesis shall be proposed by the Controller of Examinations and implemented after approval of the Vice-Chancellor.
- 21.0 Notwithstanding anything stated in this Ordinance, if the Statutory Bodies regulating the Ph.D. programme, define any condition/specification which is related to eligibility or procedure of admission, which is at variance with this Ordinance, the same shall be applicable with the approval of the Vice-Chancellor, till necessary amendments are made in this Ordinance, incorporating the said new conditions/specifications. The concerned SRC shall propose the incorporation of the same.
- 22.0 Notwithstanding anything stated in this Ordinance, for any unforeseen issues arising, and not covered by this Ordinance, or in the event of differences of interpretation, the Vice-Chancellor may take a decision, after obtaining the opinion/advice of a Committee consisting of the Director, RDC, and any or all the Deans of the Schools. The decision of the Vice-Chancellor shall be final.

This revised Ordinance shall come into force with effect from the date of approval by the Board of Management i.e. 28.04.2023.

By Order,

Dr. KAMAL PATHAK, Registrar